दमण से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

Asli Azadi Dainik @AsliAzadiDainik asliazadidainikofficial

असली आज़ादी

The Voice of Union Territory Dadra and Nagar Haveli and Daman-Diu Since 2005 www.asliazadi.com

■ वर्ष: 21, अंक: 146 ■ दमण, बुधवार 25, फरवरी 2026 ■ पृष्ठ: 8 ■ मूल्य: 2 रु ■ RNI NO-DDHIN/2005/16215 ■ संपादक- विजय जगदीशचंद्र भट्ट

केरल को 'केरलम' करने केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मोहर... केंद्र ने वामपंथी सरकार और कांग्रेस से चुनावी मुद्दा छीना

फाइल फोटो

नई दिल्ली,(ईएमएस)। आमतौर पर विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव केंद्र के पास आता है, तब उस प्रस्ताव पर लंबी बहस होती है, कई बार फाइलें अटक जाती हैं। लेकिन जब बात केरल की होती हैं, तब मामला बदल जाता है। केरल की वामपंथी (एलडीएफ) सरकार ने राज्य का नाम बदलकर 'केरल' से 'केरलम' करने का प्रस्ताव भेजा था। और मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बिना किसी लंबी खींचतान के केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की कम्युनिस्ट सरकार के प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने इतनी जल्दी मुहर लगा दी? ' सबसे पहले फैसले के समय और जगह जान लेना जरूरी है। केरल को केरलम करने का फैसला नए सेवा तीर्थ में बने पीएमओ में हुई पहली बैठक में हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसमें संविधान की पहली अनुसूची और सभी आधिकारिक भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने की मांग की गई थी। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि मोदी सरकार ने इतनी आसानी से हामी कैसे भर दी। इसके पीछे कूटनीति, राजनीति और समय का एक बहुत बड़ा मास्टरस्ट्रोक छिपा है। दरअसल यह फैसला तब आया है जब केरल में अप्रैल-मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले कई सालों से केरल में अपना सियासी आधार मजबूत करने में जुटी है। दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए केरल बीजेपी के लिए एक बहुत अहम राज्य है। केरल के लोग अपनी भाषा 'मलयालम' और अपनी संस्कृति को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। अगर मोदी सरकार इस प्रस्ताव को खारिज करती या लटकाए रखती, तब वामपंथी गठबंधन (एलडीएफ) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन (यूडीएफ) इस मामले को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना देते। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत मंजूर करके विपक्ष के हाथ से यह बड़ा चुनावी मुद्दा छीन लिया है। अब बीजेपी केरल की जनता के बीच यह कह सकती है कि हम आपकी मातृभाषा और आपकी क्षेत्रीय पहचान का पूरा सम्मान करते हैं।

'केरलम' शब्द का असली मतलब क्या है?

पहली बात, मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हमेशा से अपने राज्य को 'केरलम' ही कहते आए हैं। यह कोई नया नाम नहीं है, बल्कि यह इस जमीन का मूल नाम है। इस नाम के पीछे मुख्य रूप से दो कहानी मानी जाती हैं।

दरअसल मलयालम भाषा में 'केरा' का मतलब होता है 'नारियल का पेड़' और 'अलम' का मतलब होता है 'जमीन' या 'भूमि'। केरल में नारियल की बहुतायत है, इसलिए इन दोनों शब्दों को मिलाकर 'केरलम' बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'नारियल के पेड़ों की भूमि'।

'चेर राजवंश' से उत्पत्ति: इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यह नाम प्राचीन 'चेर' राजवंश से आया है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर चेर राजाओं का शासन था। अशोक के शिलालेखों में भी 'चेरापुत्र' शब्द का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि 'चेरम' शब्द ही समय के साथ भाषाई अपभ्रंश के कारण 'केरलम' में बदल गया।

फिर नाम 'केरल' कैसे पड़ गया?

अब सवाल यह आता हैं कि अगर मूल नाम केरलम था, तब सरकारी कागजों में यह 'केरल' कैसे बन गया? इसकी जड़ें भारत की आजादी और राज्यों के पुनर्गठन में छिपी हैं। 1 नवंबर 1956 को जब 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था, तब मलयालम बोलने वाले क्षेत्रों मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया। संविधान का मसौदा तैयार करने वाले और अंग्रेजीदां नौकरशाहों ने इसका अंग्रेजी अनुवाद 'केरल' कर दिया। वहीं उत्तर भारत और हिंदी पट्टी में इस'केरल' कहा जाने लगा। हालांकि, संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा 'मलयालम' है, लेकिन राज्य का नाम 'केरल' ही दर्ज किया।

भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस की भोपाल में किसान महाचौपाल

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा और बोले: दो दबाव में पीएम ने किया अमेरिका से ट्रेड डील

भोपाल,(ईएमएस)। राजधानी भोपाल के जवाहर चौक पर आयोजित किसान महाचौपाल में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं में जोश भरते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने अमेरिकी दबाव में ट्रेड डील किया। राहुल ने दिल्ली में गिरफ्तार हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए उन्हें 'बब्बर शेर' बताया और कहा कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां राहुल गांधी ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध हमारा अधिकार है और सच्चाई हमारे साथ है। युवाओं और किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान किसान महाचौपाल के मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, कि यह कोई सामान्य व्यापार समझौता नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया फैसला है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडाणी से जुड़े मामलों और तथाकथित 'एपस्टीन फाइल्स' के दबाव के कारण प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया। राहुल गांधी ने कहा, कि बिना व्यापक चर्चा और कैबिनेट की सहमति के अमेरिका के साथ समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को लेकर चार महीने तक बातचीत रुकी रही, क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिकी कंपनियां सोयाबीन, कपास और मक्का जैसे उत्पाद भारतीय बाजार में बेच सकें। उन्होंने कहा, देश का कोई किसान नहीं चाहता कि विदेशी कंपनियां यहां आकर बाजार पर कब्जा करें। राहुल गांधी ने कहा, कि लोकसभा में उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि वे चीन की घुसपैठ और पूर्व थलसेना प्रमुख एम. एम. नरवणे की पुस्तक में किए गए उल्लेख पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच में रोक दिया गया। उनके अनुसार, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाई गई।

खड़गे ने पीएम मोदी को सरेंडर मोदी बताया: इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और उन्हें 'सरेंडर मोदी' बताया। उन्होंने कहा, कि जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, वह केवल विपक्ष को डराने का प्रयास कर रहा है। किसान महाचौपाल में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों, विशेषकर ट्रेड डील और कृषि से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया और आगामी राजनीतिक रणनीति के संकेत दिए।

दमण-दीव सांसद उमेश पटेल ने दमणगंगा नदी प्रदूषण को लेकर पीसीसी चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन

■ सांसद उमेश पटेल ने वर्ष 2020 से 2025 तक के पर्यावरणीय आंकड़े, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रस्तुत रिपोर्टें, पीसीसी की बैठकों की कार्यवाही, वार्षिक रिपोर्टें तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए कुल व्यय और कार्यों का मांगा विस्तृत विवरण: पीसीसी से 30 दिनों के भीतर लिखित एवं दस्तावेज़ों सहित उत्तर देने की रखी मांग

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 24 फरवरी। दमण-दीव उमेश पटेल ने आज दमणगंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट के गंभीर मुद्दे को लेकर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव के प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) के चेयरमैन को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। सांसद उमेश पटेल ने अपने ज्ञापन में दमणगंगा नदी के लिए तैयार किए गए CSIR-NEERI आधारित एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति पर औपचारिक जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी), औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, ड्रेनेज इंटरसेप्शन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वायु एवं जल गुणवत्ता निगरानी तथा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ हुए पत्राचार से संबंधित विस्तृत एवं प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। सांसद उमेश पटेल ने कहा कि दमणगंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए पेयजल, मत्स्य उद्योग, तटीय पर्यटन और जनस्वास्थ्य की जीवनरेखा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि एक्शन प्लान में निर्धारित अधिकांश लक्ष्य वर्ष 2019-2020 तक पूरे किए जाने थे, लेकिन छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जमीनी स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। ज्ञापन में वर्ष 2020 से 2025 तक के पर्यावरणीय आंकड़े, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रस्तुत रिपोर्टें, पीसीसी की बैठकों की कार्यवाही, वार्षिक रिपोर्टें तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए कुल व्यय और कार्यों का विस्तृत विवरण मांगा गया है। सांसद उमेश पटेल ने स्पष्ट किया कि यह पहल किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने पीसीसी से 30 दिनों के भीतर लिखित एवं दस्तावेजों सहित उत्तर देने की मांग की है। इस ज्ञापन की एक प्रति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) नई दिल्ली को भी भेजी गई है, ताकि अंतर-राज्यीय प्रदूषण के विषय पर आवश्यक हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके।

सांसद उमेश पटेल ने दमण एवं दीव में आयोजित डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक में उठाये कई महत्वपूर्ण मुद्दे

■ सांसद उमेश पटेल ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बैंकों को उनकी सामाजिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियों की दिलाई याद

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 24 फरवरी। दमण कलेक्ट्रेट के सभागार हॉल में आज डीसीसी और डीएलआरसी की बैठक आयोजित की गई। दमण-दीव सांसद उमेश पटेल ने डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव समिति (डीसीसी) एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू समिति (डीएलआरसी) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बैठक में दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सांसद उमेश पटेल ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा बैंकों को उनकी सामाजिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियों की याद दिलाई। सांसद ने विशेष रूप से कई प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रगतिः किसानों, मछुआरों एवं पशुपालन से जुड़े लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए सांसद ने बैंकों से इस योजना के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन का आग्रह किया, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। शिक्षा ऋणः शिक्षा ऋण वितरण प्रक्रिया में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए सांसद ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शीघ्र निर्णय एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेजः स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज की सुस्त प्रगति पर चिंता जताते हुए सांसद ने महिलाओं एवं ग्रामीण समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस योजना को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोगः सांसद उमेश पटेल ने बैंकों द्वारा अपने सीएसआर फंड का दमण एवं दीव क्षेत्र में उपयोग न किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सीएसआर फंड का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे स्थानीय विकास कार्यों में किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक विकास के साथ-साथ बैंकों की सामाजिक जिम्मेदारी भी सुदृढ़ होगी। बैठक के दौरान सांसद ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की तथा जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने बैंकों को सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने एवं अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 45 दिनों के भीतर पुनः समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिक कुमार साहा ने बैठक के सफल आयोजन किया तथा सांसद उमेश पटेल की सक्रिय भागीदारी को प्रेरणादायक बताया। यह बैठक दमण एवं दीव के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है।

प्रशासक प्रफुल पटेल के मार्गदर्शन में खानवेल में रोजगार मेला का हुआ आयोजन: 453 युवाओं को मिला रोजगार

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा, 24 फरवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव प्रशासक प्रफुल पटेल के मार्गदर्शन में श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा दो दिवसीय रोजगार मेले का आज शुभारंभ हुआ। पहले दिन खानवेल में रोजगार मेला का आयोजन हुआ। जिसमें 453 युवाओं का चयन किया गया। रोजगार मेला के प्रथम चरण के अंतर्गत 24 फरवरी 2026 को खानवेल चार रास्ता के पास पुराना प्राथमिक विद्यालय में रोजगार मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस चरण में कुल 562 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से साक्षात्कार उपरांत कुल 453 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिसमें 245 पुरुष अभ्यर्थी और 208 महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया। इस दौरान चयनित युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिये गये। खानवेल में आयोजित प्रथम चरण का कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। रोजगार मेले का द्वितीय चरण 25 फरवरी 2026 को सामरवरणी पंचायत हॉल में आयोजित किया जाएगा। जिसमें दादरा नगर हवेली क्षेत्र के अभ्यर्थी भाग लेंगे। द्वितीय चरण का आयोजन कल संपन्न किया जाएगा। सभी पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

सोमनाथ ग्राम पंचायत में 25 फरवरी को कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का होगा आयोजन

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 24 फरवरी। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण दमण और एडवोकेट बार एसोसिएशन दमण तथा प्रयास के संयुक्त सहयोग से दमण जिले की सोमनाथ ग्राम पंचायत में 25 फरवरी को सुबह 10 बजे कानूनी जारगरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में वकील मयंक पटेल कानूनी जानकारी देंगे। इस दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्वास्थ्य अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए कानूनी जागरूकता, स्कील इंडिया मिशन, प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण तथा पीएम वन धन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वकील मानसी परमार नालसा (डॉन ए ड्रग फ्री इंडिया स्कीम 2025) जागरूकता एवं वेलनेस नेविगेशन के बारे में जानकारी देंगी। वकील नृति बी. राठोड नालसा - यौन उत्पीडन/अन्य अपराधों की महिला पीडित/ उत्तरजीवियों के लिए नालसा मुआवजा योजना 2018 और सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी देंगी। सामाजिक कार्यकर्ता अमोल मेश्राम बाल विवाह-2025, आशा जागरूकता समर्थन, सहायता और कार्यवाही एसओपी के बारे में जानकारी देंगे।

दर्दनाक हादसा-घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के छह लोग जिंदा जले, महिला घायल

मेरठ (एजेंसी)। यूपी के मेरठ जिले में एक मकान में आग लगने से पांच बच्चों सहित छह लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने मंगलवार को यहां बताया कि घटना किदवई नगर इलाके में बीती रात करीब आठ बजे हुई। उन्होंने बताया कि इकबाल अहमद के आवास पर आग लगने की सूचना रात आठ बजकर 49 मिनट पर मिली, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि तीन मिनट के भीतर, डायल 112 पुलिस प्रतिक्रिया वाहन मौके पर पहुंच गया और उसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। पुलिस के मुताबिक, घर में सिलाई का काम होता था और बड़ी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे जिससे आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। उन्होंने कहा कि इलाके में संकरी गलियों के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में चुनौती पेश आती है इसीलिए अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल की गईं नयी मोटरसाइकिलों को भेजा गया। एसएसपी ने बताया कि एक स्थानीय निवासी ने भी फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए सीढ़ी लगाकर बचाव प्रयासों में सहायता की। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का संदेह है और विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में सात लोग झुलसे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में चिकित्सकों ने उनमें से छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रुखसार (25), महबीश (12), हम्माद (चार), अकदस (चार), नबिया (चार माह) और इनायत (चार माह) के रूप में की गई है, जो किदवई नगर में सुराही वाली मस्जिद के पास गली नंबर तीन के निवासी थे। एसएसपी ने बताया कि घायल महिला अमीर बानो (55) का उपचार किया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य मोहम्मद फारूक ने कहा कि जब उन्हें आग लगने की सूचना मिली तो वह नमाज पढ़ने गए थे।

नीतिश के मंत्री का राहुल गांधी पर हमला, देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती

पटना (एजेंसी)। बिहार में नीतिश सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेती। राहुल गांधी की पहचान अब इसतरह के नेता के तौर पर है जो देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा हैं, लेकिन राहुल गांधी को सफलता हाथ नहीं लग रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस विरोध पर नीतिश सरकार में मंत्री पांडे ने कहा कि जब भी भारत को बदनाम करने या देश की इमेज खराब करने के लिए कांग्रेस सबसे आगे रहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेजी से मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। इसकारण भारत की जनता राहुल गांधी को कभी गंभीरता से नहीं लेती। मंत्री पांडे ने कहा कि एआई समिट विश्व का मंच था, जहां 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वहां जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, वह निंदनीय है। कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से सभी को बहुत आघात पहुंचा है। कांग्रेस के लोग पता नहीं कि अब लोकतंत्र में क्या दिखाना क्या चाहती है। कांग्रेस ने शर्टलेस प्रोटेस्ट से देश की छवि को खराब करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर कहा कि आपने देखा कि एआई समिट में 140 देशों के प्रतिनिधियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा था और किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा एक छोटी-सी बात को लेकर भारत की छवि को दुनिया के सामने खराब करने की कोशिश की गई।

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने पर 13 छात्रों को नोटिस

लखनऊ (एजेंसी)। रमजान के महीने में लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाल बारादरी में नमाज पढ़ने के प्रकरण में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर 13 छात्रों को नोटिस दे दिया है। सहायक पुलिस आयुक्त/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट, महानगर कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत जारी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि संबंधित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में लाल बारादरी के पास चल रहे निर्माण कार्य को बाधित करने का काम किया। कैंटीन के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हुई। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जारी आदेश में कहा गया है कि इन गतिविधियों से विश्वविद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने सभी 13 छात्रों को निर्देश दिया है कि वे एक वर्ष तक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के रूप में 50 हजार का व्यक्तिगत मुचलका और 50-50 हजार के दो जमानतदार प्रस्तुत करें। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर की लाल बारादरी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हिंदू छात्रों ने चेन बनाकर मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने में मदद की थी। सोमवार को छात्रों के दूसरे संगठन ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। आरोप है कि लाल बारादरी में रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसके बावजूद छात्र यहां नमाज अदा करने पहुंचे थे। जब छात्रों को नमाज पढ़ने से रोका गया तब हिंदू छात्रों ने बैरिकेटिंग को गिरा दिया और ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद छात्रों ने नमाज अदा की और रोजा खोला।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर महंगे आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा के साथ महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर एक महिला यात्री को अवैध रूप से महंगे आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा लाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अमेरिकी पासपोर्ट धारक यह महिला हांगकांग से फ्लाइट नंबर सीएक्स-695 द्वारा टर्मिनल-3 पर पहुंची थी। महिला पर संदेह होने पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन्हें रोका और सामान की एक्स-रे जांच की। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत विस्तृत तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अघोषित विदेशी सामान बरामद हुआ।

बंगाल के एसआईआर में लाखों दावों-आपत्तियों से निपटेंगे झारखंड-ओडिशा के जज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर में 80 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए सिविल जजों को नियुक्त करने और पड़ोसी राज्यों झारखंड व ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को बुलाने की अनुमति दे दी है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एक पत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि एसआईआर कवायद के लिए तैनात 250 जिला न्यायाधीशों को दावों और आपत्तियों से निपटने में करीब 80 दिन लगेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर स्थिति और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए पीठ ने प्रक्रिया संचालित करने के लिए सिविल जजों की तैनाती की अनुमति दी। उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से झारखंड और ओडिशा के अपने समकक्षों से

अनुरोध करने और स्थिति से निपटने के लिए समान पदों के न्यायिक अधिकारियों की मांग करने को कहा। पीठ ने निर्वाचन आयोग को झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का खर्च वहन करने का निर्देश भी दिया। हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति भी दी और स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया आगे बढ़ने पर चुनाव आयोग पूरक सूचियां जारी कर सकता है। वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पारिवारिक संबंध जोड़ने में तार्किक विसंगतियों में ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें माता-पिता के नाम में असंगति पाई गई है और मतदाता व उसके माता-पिता के बीच आयु का अंतर 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच गतिरोध से निराश होकर राज्य में विवादों से घिरे एसआईआर में आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का एक निर्देश जारी किया था। चुनाव आयोग और बंगाल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई टीएमसी सरकार के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप और विश्वास की कमी पर अफसोस जताते हुए पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई नए निर्देश पारित किए थे।

गुटखे के प्रचार को लेकर हाईकोर्ट सख्त, शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार को भी बनाया पक्षकार

लखनऊ (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में अपने पूर्व के आदेश के पालन के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान प्राधिकरण से पूछा था कि 2023 में याची के प्रत्यावेदन पर अब तक जांच लंबित क्यों है? याचिका में गुटखा कंपनियों के साथ क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल तथा अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रितिक रोशन, टाइगर श्राफ, सैफ अली खां व रणवीर सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये हस्तियां जो पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर रही हैं उनमें से अधिकांश पद्म पुरस्कार धारक हैं और उनकी ओर से किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों से समाज में गलत संदेश जाता है। ये विज्ञापन उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन भी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन चुके: अनुराग ठाकुर

कांगड़ा (एजेंसी)। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन चुके हैं। कांगड़ा में भाजपा सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बने हुए हैं। वह भारत में रहकर और भारत के बाहर रहकर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, इतना ही नहीं नकारात्मक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देकर अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। अब उनका एकमात्र काम झूठ बोलना, कन्फ्यूजन पैदा करना, भारत को बदनाम करना और मोदी विरोधी राजनीति करना है। जब भारत की इकॉनमी सबसे तेजी से बढ़ रही है, तब वह भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहते हैं। उन्हें भारत की तरक्की पसंद नहीं है। भाजपा सांसद ने कहा कि पूरी दुनिया ने एआई समिट की तारीफ की, वहां राहुल गांधी के इशारे पर उनके कार्यकर्ता शर्टलेस प्रदर्शन कर देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। क्या राहुल गांधी की राजनीति विदेशों से तय हो रही है। कांग्रेसी विदेशियों का एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जॉर्ज

सोरेस के कहने पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा ले रही है और फिर चीन का गुणगान कर रही है।

उन्होंने कहा कि आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुडदंग, ल से लंफगई। उनकी जगहंसाई हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सच में नेता प्रतिपक्ष हैं।

भाजपा सांसद ने कहा कि संसद में महिला सांसदों को भेजकर पीएम की सीट का घेराव करना किस तरह की राजनीति है। विदेशी मंचों पर जाकर राहुल गांधी बयान देते हैं। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, उनका यही काम रह गया है। कांग्रेस अराजकता, अफवाह और दंगा फैलाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जो सोच रहे हैं, वह सफल नहीं हो सकते है।

कांग्रेस डरपोक नहीं, संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा करेंगे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया

बेंगलुरु (एजेंसी)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि वे हमारे युवा नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस न तो डरपोक है और न ही डरने वाली है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे।

बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में खड़गे ने कहा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, तो नितिन गडकरी और बीजेपी नेताओं ने क्या किया? ऐसे हर इवेंट में वे देश की भावना को समझने में नाकाम रहे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे उस समय भारत और विदेश के एथलीटों को क्या संदेश जाएगा। बीजेपी दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकती है। अगर वे अपने गिरेबान में झांकेंगे, तो शायद उन्हें अपनी सच्चाई दिखाई देगी। मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष

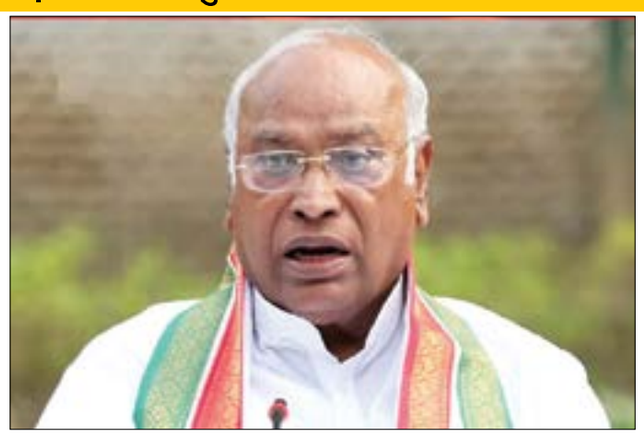

भानु की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं।

रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने कहा कि युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश का माहौल इतना खराब हो चुका है कि उसके कारण केंद्र सरकार के प्रति लोगों में भारी रोष है। मैं चाहता था कि पीएम मोदी देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार वह कर रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील से किसानों का नुकसान होगा। हमें बंधुआ मजदूर बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है।

खड़गे ने कहा कि सरकार की ओर से कांग्रेस को डराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है और न ही डरपोक है। हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे। हम लड़ते रहेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि प्रदर्शन करने के बाद अगर हिरासत में लिया जाता है तो पुलिस कुछ देर बाद छोड़ देती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को निशाना बनाकर डर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस डरने वाली नहीं है।

केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने पर थरुर का मजाकिया अंदाज

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने एक दिलचस्प लेकिन अहम भाषाई सवाल उठा दिया है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने अपनी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर कहा कि नाम परिवर्तन सभी के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए एक छोटा सा भाषाई प्रश्न खड़ा होता है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज़ में पूछा कि अगर राज्य का नाम 'केरलम' हो जाएगा, तब वहां के निवासियों को क्या कहा जाएगा....केरलाइट', 'केरलन' या कुछ और?

कांग्रेस सांसद थरूर ने मजाकिया लहजे में लिखा कि 'केरलमाइट' शब्द सुनने में किसी सूक्ष्म जीव (माइक्रोब) जैसा लगता है, जबकि 'केरलमियन' किसी दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ मटीरियल) की तरह प्रतीत होता है। उन्होंने केरल के सीएम ऑफिस को टैग कर सुझाव दिया कि शायद मुख्यमंत्री नए शब्द के चयन के लिए कोई प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। उनका यह बयान तब आया है जब केंद्र की मोदी सरकार राज्य का नाम आधिकारिक रूप से 'केरलम' करने सहमति जता चुकी है।

महाराष्ट्र से एनसीपी पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उतारेगी, बीजेपी के अंदर नामों को लेकर मंथन

-शिवसेना शिंदे गुट के लिए एक सीट सुरक्षित

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत में हलचल तेज हो गई है। महायुति की सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने इस लेकर अपने उम्मीदवार पर बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, सोमवार की रात प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी की कोर कमेटी की हुई बैठक में पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उतरने पर सहमति बनी है। बैठक में प्रफुल्ल पटेल के अलावा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। 26 फरवरी को होने वाली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लग सकती है, जहां सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भी अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पार्टी इस बार राज्यसभा की चार सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसमें रामदास अठावले का नाम करीब तय है, जबकि विनोद तावड़े, विजया रहाटकर और धैर्यशील पाटिल के नामों पर

अंतिम निर्णय होना बाकी है।

बात दें कि महाराष्ट्र में इस बार राज्यसभा की 7 सीटें खाली हैं और 286 विधायकों के आधार पर एक उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। आंकड़ों के अनुसार, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पास स्पष्ट बढ़त है। सिर्फ बीजेपी के पास एक निर्दलीय को मिलाकर कुल (131+1) यानी 132 विधायकों का समर्थन है, इस संख्याबल के दम पर 3 से 4 सांसद आसानी से भेज सकती है। वहीं शिवसेना (शिंदे गुट) अपने 58 विधायकों के साथ एक सीट सुरक्षित कर सकती है, जबकि एनसीपी (अजित पवार गुट) भी एक सीट जीतने की स्थिति में है, क्योंकि अजित पवार की मौत के बाद उसके पास 40 विधायक हैं।

इसके मुकाबले महाविकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (ठाकरे गुट) शामिल हैं, के पास कुल मिलाकर करीब 49 विधायकों का समर्थन है। इस संख्या के आधार पर एमवीए केवल एक सीट ही सुरक्षित कर सकती है। राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से महायुति गठबंधन 6 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन को सीमित सफलता मिलने की संभावना है।

उड़ान भरते ही विमान इंजन हुआ फेल, दिल्ली एसरपोर्ट पर कराई आपात लैंडिंग

-कॉकपिट में नहीं मिला फायर वार्निंग संकेत, विमान में सवार थे 150 यात्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से लेह जा रहे स्पाइस जेट विमान की मंगलवार उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण लेह जाने के बजाय दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे। इस घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इंजन नंबर-2 फेल होने से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के बाद यात्रियों के लिए यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था की उम्मीद है। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली से लेह जा रहे विमान को वापस बुलाना पड़ा। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कॉकपिट में फायर वार्निंग का कोई संकेत नहीं मिला।

रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ्लाइट एसजी121 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से

निकली थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रू मेंबर्स को तकनीकी खराबी का पता चला। सावधानी बरतते हुए पायलटों ने विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला लिया। विमान की पूरे प्रोटोकॉल के साथ लैंडिंग करवाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ मेडिकल टीम और फायर सर्विस भी वहां मौजूद थी।

बता दें इससे पहले असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइन के एक विमान में 14 फरवरी को बम होने की धमकी मिली थी जिसके बाद विमान की तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। वहीं बीते साल 2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो के एक विमान में बम की धमकी के बाद मुंबई में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। विमान में बम की चेतावनी की धमकी ई-मेल से मिली थी जो कि बाद में फर्जी निकली। वहीं बीते साल ही 12 नवंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुंबई से वाराणसी जा रहे विमान के टॉयलेट में कागज पर बम लिखा मिलने के बाद वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी।

कांग्रेस गुटबाजी, अविश्वास और सहयोगी दलों के साथ तालमेल की कमी से हाशिये पर!

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफा देने के बाद पार्टी की लगातार गिरती राजनीतिक स्थिति और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। बोरा ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक कलह तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई राज्यों में कांग्रेस की इकाइयां अंदरूनी गुटबाजी, आपसी अविश्वास और सहयोगी दलों के साथ तालमेल की कमी के कारण हाशिये पर आ रही है। आलोचकों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व की निर्णय प्रक्रिया में कथित 'सुस्ती' और समय पर हस्तक्षेप न कर पाने की प्रवृत्ति पार्टी के लगातार क्षरण का कारण बन रही है।

कर्नाटक में सीएम सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संतुलन को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। बताया जाता है कि राहुल गांधी की मुलाकातों के बावजूद मतभेद खत्म नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह गुटों के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर संघर्ष जारी है। पार्टी ने राज्य इकाई भंग कर संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन असंतोष बना रहा। दिल्ली में जहां कभी शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, पार्टी आज एकजुट चेहरा पेश करने में नाकाम है।

वहीं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मतभेदों ने 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन तब तक काफी क्षति हो चुकी थी। यूपी में संगठन भंग करने के बावजूद कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं हो पाई। पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश में भी पार्टी अव्यवस्था का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ गठबंधन भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका।

बिहार में राजद के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को 'बोझ' के रूप में देखा गया। ओडिशा में संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव को 2023 में सत्ता गंवाने की बड़ी वजह माना गया। गुजरात और महाराष्ट्र में भी पार्टी दो दशक से ज्यादा समय से बीजेपी को चुनौती देने में विफल रही है। तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गठबंधन के बावजूद सीट बंटवारे को लेकर मतभेद उभरे हैं, जिससे आगामी चुनावों से पहले असहज स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर कई राज्यों में लगातार गुटबाजी, नेतृत्व संकट और सहयोगियों के साथ तालमेल की कमी ने कांग्रेस की स्थिति को कमजोर किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनौतियों के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है।

पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए पहले दौर की बातचीत

नई दिल्ली (ईएमएस)। पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के लिए पहले दौर की बातचीत 23 फरवरी से शुरू हो गई है और यह 26 फरवरी तक चलेगी। यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से दी गई। दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए पिछले साल नवंबर 2025 में तेल अवीव में टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) भी साइन किया, जो दोनों के बीच चल रही एफटीए की बातचीत को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ था। भारत और इजरायल कई क्षेत्रों में एक-दूसरे के पूरक हैं, और यह एफटीए लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित व्यवसायों को निश्चितता और पूर्वानुमान प्रदान करके द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम करेगा। इस राउंड के दौरान, दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ एफटीए के विभिन्न पहलुओं जैसे कि वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि को कवर करने वाले सत्रों में भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25-26 फरवरी, 2026 को होने वाली इजरायल यात्रा के अवसर पर एफटीए की वार्ता शुरू हुई है। अग्रवाल ने नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एआई, साइबर सुरक्षा, उच्च-तकनीकी विनिर्माण, कृषि और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण अवसरों पर जिक्र किया। साथ ही कहा कि एफटीए दोनों देशों को इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इजरायल की ओर से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की मुख्य वार्ताकार, इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार प्रशासन में व्यापार नीति और समझौतों की वरिष्ठ निदेशक और उप व्यापार आयुक्त यिफात अलोन पेरेल ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इस एफटीए में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के लिए नए बाजार खोलने की क्षमता है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के 8 जिलों में रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ाने संबंधी तीन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी

■ भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी ■ कुल 9,072 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी ■ इनमें पुनारख-किउल के मध्य तीसरी और चौथी लाईन के निर्माण को भी मिली मंजूरी

हाजीपुर, (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार को रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ाने संबंधी तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इनमें पुनारख-किऊल तीसरी और चौथी लाइन, गोंदिया-जबलपुर लाइन दोहरीकरण एवं गम्हरिया-चांडिल तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में व्याप्त इन तीन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 5,407 गांवों में संपर्क में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 98 लाख है। विदित हो कि रेल यात्रा सुगम हो साथ ही मालगाड़ी की आवाजाही भी सुगमतापूर्वक किया जा सके इसके लिए रेलवे द्वारा रेल आधारभूत संरचना में वृद्धि का कार्य निरंतर जारी है। इसी कड़ी में 17 हजार करोड़ रूपए की लागत से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-झाझा के मध्य लगभग 400 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाईन का निर्माण किया जाना है जिसमें वर्तमान में डीडीयू से किउल तक तीसरी और चौथी रेल लाइन जबकि किउल से झाझा तक तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जाना है। इस पूरी परियोजना को कई हिस्सों में बांटा गया है तथा रेलवे बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। निर्माण कार्य सुगमतापूर्वक तेजी से पूरा करने के लिए इसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल तथा किऊल-झाझा जैसे छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटा गया है। इसके तहत प्रथम चरण में फतुहा से बख्तियारपुर (24 किमी) तथा बख्तियारपुर से पुनारख (30 किमी) की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान कर दी गयी थी जिसमें बख्तियारपुर-पुनारख निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मंगलवार को 50 किमी लंबे पुनारख से किउल के मध्य तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। शेष रेलखंडों की स्वीकृति विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-झाझा रेल लाईन का निर्माण 1860-70 के दशक में किया गया था। तत्पश्चात इसका दोहरीकरण किया गया। तब से अब तक कई दशकों के मध्य जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकीकरण के मद्देनजर यात्री गाड़ियों के साथ-साथ मालगाड़ियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती चली गयी। इसके फलस्वरूप ट्रैकों की क्षमता से कई गुणा अधिक गाड़ियों के परिचालन से ट्रैकों के रख-रखाव एवं समय पालन में कठिनाइयां आती थीं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ट्रैकों की क्षमता में वृद्धि अति आवश्यक था। इन्हीं के मद्देनजर मालगाड़ियों के परिचालन हेतु पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर तथा तीसरी एवं चौथी लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इन लाइनों के निर्माण से मालगाड़ी के साथ-यात्री गाड़ियों का परिचालन सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा साथ ही काफी संख्या में अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा इससे ये कनेक्टिविटी मजबूत होगी जो औद्योगीकिरण वृद्धि में सहायक होगा। इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी।

मेटा के आंतरिक सर्वे में किशोरों की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा

■हर 5 में से 1 टीनएजर ने इंस्टाग्राम पर देखी आपत्तिजनक तस्वीरें

नई दिल्ली(ईएमएस)। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किशोरों की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अदालत में पेश दस्तावेजों के मुताबिक, 13 से 15 वर्ष के करीब 19 प्रतिशत यूजर्स ने बताया कि उन्हें ऐसे आपत्तिजनक या यौन तस्वीरें दिखीं, जिन्हें वे देखना नहीं चाहते थे। यह जानकारी अमेरिका के कैलिफोर्निया में चल रहे एक फेडरल मुकदमे के दौरान सार्वजनिक हुई। दस्तावेजों में मार्च 2025 में इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी की गवाही के अंश भी शामिल हैं। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन के अनुसार, यह आंकड़ा 2021 में इंस्टाग्राम यूजर्स पर किए गए एक सर्वे से आया था। यह किसी पोस्ट की सीधी जांच पर आधारित नहीं था, बल्कि यूजर्स के अनुभवों पर आधारित सर्वे था। सर्वे में यह भी सामने आया कि 13 से 15 साल के लगभग 8त्न किशोरों ने कहा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर किसी को खुद को नुकसान पहुंचाते या ऐसा करने की धमकी देते देखा। किशोरों को प्रभावशाली यूजर मानती है कंपनी अदालत में पेश किए गए एक अन्य दस्तावेजों से पता चला है कि मेटा के शोधकर्ता किशोरों को अपने मंच के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। जनवरी 2021 के एक मेमो में एक शोधकर्ता ने सुझाव दिया था कि कंपनी को किशोरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे अपने घर के लिए कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक किशोर एप का इस्तेमाल करता है, तो वह अपने माता-पिता और छोटे भाई-बहनों को भी इससे जोडऩे के लिए प्रभावित करता है। कंपनी का मानना था कि नए यूजर्स हासिल करने और उन्हें बनाए रखने के लिए बच्चों के जरिए पूरे परिवार तक पहुंचना एक बेहतरीन रणनीति है। मेटा पर बढ़ता कानूनी दबाव मेटा प्लेटफॉर्म्स, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक है, पर दुनियाभर में आरोप लग रहे हैं कि उसके प्लेटफॉर्म युवा यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका में कंपनी पर हजारों मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें आरोप है कि मेटा ने जानबूझकर अपने एप्स को नशे की तरह लत लगाने वाला बनाया है, जिससे नाबालिगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इन आरोपों के जवाब में इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी का तर्क है कि ज्यादातर आपत्तिजनक सामग्री प्राइवेट मैसेज के जरिए भेजी जाती है। उनके अनुसार, कंपनी के लिए चुनौती यह है कि वे सुरक्षा के नाम पर लोगों के निजी मैसेज नहीं पढ़ सकते क्योंकि इससे यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। बढ़ते दबाव के चलते मेटा ने नीतियों में किए बदलाव हालांकि, बढ़ते दबाव के बीच 2025 के अंत में मेटा ने अपनी नीतियों में कुछ कड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने अब एआई द्वारा तैयार की गई आपत्तिजनक या यौन सामग्री को पूरी तरह से हटाने का वादा किया है, बशर्ते वह मेडिकल या शैक्षिक उद्देश्य के लिए न हो। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन का कहना है कि कंपनी सुरक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रही है और इसे और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम जारी है। दुनियाभर में बढ़ रही है सोशल मीडिया पर सख्ती दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया है। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। डेनमार्क की असेंबली ने नवंबर 2025 में 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने का समझौता किया गया। हालांकि, 13-14 साल के बच्चों को माता-पिता की अनुमति से छूट देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस साल जनवरी में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का बिल पास किया। मलेशियाई सरकार ने भी सभी प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए बैन करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, स्पेन ने भी 16 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस बंद करने की योजना की घोषणा की है। ग्रीस और स्लोवेनिया भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का बिल ला सकते हैं। वहीं, नॉर्वे में सोशल मीडिया के लिए सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर 15 करने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 में बच्चों और किशोरों में बढ़ती सोशल मीडिया की लत पर चिंता जताई गई है। सर्वेक्षण में सोशल मीडिया एप्स के लिए उम्र के हिसाब से सीमाएं तय करने और प्लेटफॉर्म्स को सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की गई है।

बुजुर्गों की पेंशन कटने की बातें पूरी तरह अफवाह... ऐसा करके कांग्रेस पाप कर रही

गुरुग्राम (ईएमएस)। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने की बातें पूरी तरह अफवाह हैं और विपक्ष हरियाणा राज्य में इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर पाप कर रहा है। वे हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग समाज के सम्मानित सदस्य हैं और उनकी सुरक्षा व सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प पत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। यदि वे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, तब उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता सुनिश्चित की गई है, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पेंशन बंद नहीं की, बल्कि उसमें बढ़ोतरी कर बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाया है। अब पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है और लाभार्थियों को मोबाइल पर एसएमएस से सूचना आती है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधकर कहा कि पहले बुजुर्गों को महीनों तक पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में शिकायत आती है, तब सत्यापन के दौरान पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जाती है, लेकिन प्रक्रिया पूरी होते ही राशि जारी कर दी जाती है। हरियाणा सरकार ने पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था लागू की है।

व्हाट्सऐप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह बिना स्पष्ट सहमति के डेटा साझा नहीं करेगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप्स में से एक व्हाट्सऐप ने प्राइवेसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख नरम किया है। कंपनी ने कहा है कि वह यूजर्स का डेटा उनकी स्पष्ट मंजूरी के बिना साझा नहीं करेगी और नियामकों के निर्देशों का पालन करेगी। इसे कंपनी का यू-टर्न माना जा रहा है, क्योंकि 2021 में लाई गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कंपनी पहले काफी आक्रामक रुख में थी। साल 2021 में व्हाट्सऐप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की। इस पॉलिसी में कहा गया था कि बिजनेस अकाउंट्स और कुछ अन्य सेवाओं के लिए यूजर्स का डेटा उसकी पैरेंट कंपनी टी३ ढ'३ङ्ग१२ क्लू। के साथ साझा किया जा सकता है। कई यूजर्स और जानकारों ने इसे टेक इट ऑर लीव इट मॉडल बताया। यानी अगर आपको व्हाट्सऐप इस्तेमाल करना है तो शर्तें माननी ही होंगी वरना इस ऐप को आप छोड़ दें। इसका व्यापक विरोध हुआ और मामला नियामक संस्थाओं और अदालतों तक पहुंच गया। यहां पर इस मामले में कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दखल दिया। आयोग ने पाया कि व्हाट्सऐप ने अपनी मजबूत बाजार स्थिति का फायदा उठाया और यूजर्स को नई शर्तें मानने के लिए मजबूर किया। उउक ने ऐप पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा दिया और डेटा शेयरिंग के तरीके में बदलाव के निर्देश दिए। व्हाट्सऐप ने इस आदेश को चुनौती दी और मामला नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल तक गया। वहां कुछ राहत मिली, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने साफ कहा कि यह सिर्फ जुर्माने का मामला नहीं है- यह नागरिकों के मौलिक अधिकार, खासकर निजता के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या यूजर्स को साफ और स्वतंत्र विकल्प दिया गया था? क्या वे बिना दबाव के 'ना कह सकते थे? ताजा सुनवाई में व्हाट्सऐप ने कहा वह बिना स्पष्ट सहमति के डेटा साझा नहीं करेगा, यूजर्स को डेटा शेयरिंग पर कंट्रोल दिया जाएगा और नियामक आदेशों का पालन किया जाएगा। इसे ही व्हाट्सऐप के रुख में यू-टर्न के तौर पर देखा जा रहा है।

सायबर ठगी का बड़ा खुलासा: सोमनाथ मंदिर के नाम पर हाईटेक गैंग ने श्रद्धालुओं से ठगे लाखों रुपये

■ पुलिस ने राजस्थान के एक कॉलेज के 6 छात्रों को किया गिरफ्तार, एआई टूल्स से बनाई थी नकली वेबसाइट

अहमदाबाद (ईएमएस) द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ठगने वाली एक हाईटेक साइबर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गांधीनगर साइबर क्राइम सेल ने 6 लोगों की इस गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसने सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित अतिथिगृहों के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लाखों रुपये की ठगी की। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने सोमनाथ ट्रस्ट के तीन प्रमुख अतिथिगृह - सागर दर्शन, महेश्वरी और लीलावती के नाम से फर्जी वेबसाइट तैयार की थी। ये वेबसाइट इतनी पेशेवर और असली जैसी दिखती थी कि आम श्रद्धालु असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते थे। आरोपियों ने ठगी को अंजाम देने के लिए मशहूर ट्रैवल प्लेटफॉर्म अगोड़ा का भी दुरुपयोग किया। इतना ही नहीं, गैंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स का इस्तेमाल कर प्रोफेशनल कंटेंट और वेबसाइट डिजाइन तैयार की, ताकि फर्जी लिंक सर्च इंजन में ऊपर दिखाई दें और श्रद्धालु आसानी से जाल में फंस जाएं। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि अब तक करीब 20 लाख रुपये से अधिक की ठगी की जा चुकी है। केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी कुल 90 शिकायतें दर्ज हुई हैं। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह सिर्फ सोमनाथ तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम पर भी फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर एडवांस भुगतान वसूलता था। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी राजस्थान के एक कॉलेज के छात्र हैं। अधिक पैसे कमाने की लालच में पढ़े-लिखे युवाओं ने अपराध का रास्ता चुना। घटना के बाद सोमनाथ ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही बुकिंग करें। किसी भी अनजान प्लेटफॉर्म या थर्ड पार्टी ऐप पर भुगतान करने से पहले उसकी सत्यता की पूरी जांच अवश्य करें।

UT Administration of Dadra Nagar Haveli and Daman & Diu

Health Department, Diu

Walk in interview for following post Under RKS Govt. Hospital-Diu

Hospital Administrator/Manager-1

Notice No. : GHD/ADM/RKS/letter/2025-26/731
Notice Date 21/02/2026
Date of Interview : 11/03/2026 (01:00 PM)
Venue : Collectorate-Diu.

For details, please scan or visit diu.gov.in 02875-252480

Govt. Hospital-Diu

NO:IP/DMN/2/5/2025-26/1189 DATE :- 24/02/2026

Advocate for applicant: Maulik N. Paida
Next date: 16/03/2026

PUBLIC NOTICE

IN THE COURT OF THE HON'BLE CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION, DIU, AT: DIU.

CNR-UTDD02-000116-2026
C. M. A. No. 69/2026

Bhavneshkumar Nanu & 1 Anr .... Applicant/s

Vs

The Civil Registrar Diu. .... Opponent/s

The public at large to take note that applicants above named have filed application for rectification of their marriage records under Article 3 read with article 97 & 98 of Portuguese Civil Registration Code.

Whereas they intendant to rectify the date of marriage / their names / their parent names previously registered in the record of marriage kept and preserved by Civil Registrar Office, Diu, against Marriage **Entry No. 611/2009, dated: 08/12/2009.**

Therefore, if anybody has any objection for rectification of the marriage record of Civil Registrar Diu, shall appear either in person or through advocate and file written objection within 30 days of publication of this notice. If objection of whatsoever nature is not registered before this Hon'ble Court, then necessary order will be passed and objection if any raised afterwards shall not be considered.

Place: Diu.
Date: 23/02/2026

By Order

A.S. / Superintendent,
Diu

CIVIL JUDGE, S.D., COURT • DIU •

दर्दनाक हादसा-घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के छह लोग जिंदा जले, महिला घायल

मेरठ (ईएमएस)। यूपी के मेरठ जिले में एक मकान में आग लगने से पांच बच्चों सहित छह लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने मंगलवार को यहां बताया कि घटना किदवई नगर इलाके में बीती रात करीब आठ बजे हुई। उन्होंने बताया कि इकबाल अहमद के आवास पर आग लगने की सूचना रात आठ बजकर 49 मिनट पर मिली, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि तीन मिनट के भीतर, डायल 112 पुलिस प्रतिक्रिया वाहन मौके पर पहुंच गया और उसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। पुलिस के मुताबिक, घर में सिलाई का काम होता था और बड़ी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे जिससे आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। उन्होंने कहा कि इलाके में संकरी गलियों के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में चुनौती पेश आती है इसीलिए अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल की गईं नयी मोटरसाइकिलों को भेजा गया। एसएसपी ने बताया कि एक स्थानीय निवासी ने भी फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए सीढ़ी लगाकर बचाव प्रयासों में सहायता की। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का संदेह है और विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में सात लोग झुलसे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में चिकित्सकों ने उनमें से छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रुखसार (25), महबीश (12), हम्माद (चार), अकदस (चार), नबिया (चार माह) और इनायत (चार माह) के रूप में की गई है, जो किदवई नगर में सुराही वाली मस्जिद के पास गली नंबर तीन के निवासी थे। एसएसपी ने बताया कि घायल महिला अमीर बानो (55) का उपचार किया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य मोहम्मद फारूक ने कहा कि जब उन्हें आग लगने की सूचना मिली तो वह नमाज पढ़ने गए थे।

एम्स में डॉक्टर से अभद्रता, 2 गिरफ्तार

गोरखपुर(ईएमएस)। गोरखपुर के एम्स में काम करने वाली नागालैंड की 25 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ छेडख़ानी और गाली-गलौज करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने मॉल से लौट रही पीड़िता का पीछा किया, जहां वो खरीदारी के लिए गई थी। उन्होंने एम्स के एंट्रेंस के पास उसे गलत तरीके से छूने से पहले कथित तौर पर रास्ते भर छींटाकशी की। गोरखपुर एसपी अभिनव त्यागी ने कार्रवाई के संबंध में कहा कि इस मामले में तीन लोगों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। इधर, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के साथ नस्लीय भेदभाव और यौन उत्पीडऩ सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होनी चाहिए, इसे सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए, भुला नहीं दिया जाना चाहिए और हर बार जब कोई नई घटना सामने आती है तो इसे फिर से जिंदा नहीं किया जाना चाहिए।

छह अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी

कोलकाता(ईएमएस)। पश्चिम बंगाल में उस समय हडक़ंप मच गया, जब एक साथ राज्य के छह अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी कोलकाता के सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट और बैंकशाल कोर्ट को एक ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली। मेल में दावा किया गया था कि अदालत परिसर में बम लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, स्निफर डॉग और बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया। घंटों तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक नहीं मिला। इसी तरह की धमकी हुगली जिले के चिनसुराह कोर्ट, पश्चिम बर्दवान के आसनसोल और दुर्गापुर कोर्ट तथा मुर्शिदाबाद के बेरहामपुर कोर्ट को भी मिली। सभी जगह लगभग एक ही समय पर ऐसे ई-मेल भेजे गए, जिससे हडक़ंप मच गया। मेल में दावा किया गया था कि अदालत परिसर में आरडीएक्स से बना आईईडी बम लगाया गया है और उसे दोपहर 12 बजे रिमोट के जरिए उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिलते ही आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर कोर्ट परिसर को खाली कराया। सभी लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेज दिया गया।

मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक

ललित गर्ग

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं।

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने है, इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है।

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहां से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता

है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर पड़ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता पनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्वत देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मयार्दा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें।

यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दशार्ता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंततः उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पूछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्ममंथन का है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं। यदि इन पर निवेश बढ़ेगा, तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य पर बोझ कम होगा। वहीं, नागरिकों को भी यह ठानना होगा कि वे तात्कालिक प्रलोभनों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र की सुदृढ़ता तभी सुनिश्चित होगी जब शासन और जनता दोनों अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

निस्संदेह, चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा है, यही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

संपादकीय

शंकराचार्य बनाम साधु

तिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप अश्लील हैं कि उन्होंने और उनके शिष्य ने दो नाबालिग शिष्यों का यौन शोषण किया। जो आशुतोष ब्रह्मचारी नामक कथित साधु ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी, वह भी एक और संन्यासी, कथित जगद्गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताया जा रहा है। अदालत में जज के सामने धारा 164 के तहत नाबालिग शोषितों के बयान भी दर्ज करा दिए गए हैं। पॉक्सो की विशेष अदालत ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। चूंकि मामला पॉक्सो का है, लिहाजा बेहद संवेदनशील है। क्या शंकराचार्य को जेल भी भेजा जा सकता है? यदि ऐसा हुआ, तो बड़ा धार्मिक वज्रपात होगा, क्योंकि शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सनातन के शिखर-पुरुष हैं, सर्वोच्च धर्मगुरुओं में शामिल हैं। जिस साधु-संत के असंख्य श्रद्धालु हैं, उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें ह्यभगवानह्ण मान कर प्रणाम करते हैं, एक और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, शंकराचार्य के ही, बटुकों की शिखा खींचने को ह्यमहापापह्ण करार देते हैं और अपने आवास पर बटुकों का सम्मान करते हैं, उसी शख्स के शंकराचार्य होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए थे। आश्चर्य है कि उप्र में यह क्या हो रहा है? हिंदुत्व और सनातन की कट्टर समर्थक, पैरोकार भाजपा की सरकार में सनातन-पुरुष पर ही घमासान क्यों मचा है?

जो अभी तक शंकराचार्य हैं, जिनके पदनाम पर सर्वोच्च अदालत ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, जो शंकराचार्य सनातन के शिखर संतों में एक हैं और आदि शंकराचार्य की प्रतिमूर्ति हैं, उन्हें ही दुराचारी और बलात्कारी करार क्यों दिया जा रहा है? इन आरोपों की तुलना आसाराम बापू के केस से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें बलात्कार की निरंतर पीड़िता नाबालिग कन्या के परिजनों ने भी शिकायतें दर्ज कराई थीं। मीडिया के सामने आकर दुष्कर्म-कथा सुनाई थी। आसाराम को ह्यभगवानह्ण मानने वालों की भी कमी नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक उनके ह्यभक्तह्ण थे। मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की आस्था, श्रद्धा भी उनके प्रति थी। आसाराम कई सालों से जेल में हैं। बीते दिनों स्वास्थ्य आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।

चिंतन-मनन

कहीं आप भी पाप की पूंजी तो जमा नहीं कर रहे

क्या आपने कभी किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरूद्ध आवाज उठायी है। किसी कमजोर और लाचार को पिटता देखकर मदद के लिए आगे आएं हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो समझ लीजिए आपने अपने खाते में पाप की पूंजी जमा कर ली है। जिस प्रकार से पाप और पुण्य को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार जो व्यक्ति किसी को कष्ट में देखकर उसकी मदद नहीं करता है। किसी के भय से अथवा अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोलता है और शरण में आये व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है वह पापी है।

इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। एक थे राजा शिवि। इनके धार्मिक स्वभाव और दयालुता एवं परोपकार के गुण की ख्याति स्वर्ग में भी पहुंच गयी। इन्द्र और अग्नि देव ने योजना बनायी कि राशि शिवि के गुणों को परखा जाए। एक दिन अग्नि देव कबूतर बने और इन्द्र बाज। कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवि की गोद में आकर बैठ गया और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। इसी बीज बड़ा सा बाज राजा शिवि के पास पहुंचा और कबूतर को वापस करने के मांग करने लगा। बाज ने कहा कि, कबूतर मेरा आहार है अगर आप मुझे वापस नहीं करेंगे तो आपको मुझे भूखा रखने का पाप लगेगा।

बाज की बातों को सुनकर राजा शिवि ने कहा कि कबूतर मैं तुम्हें नहीं दूंगा अगर कोई अन्य उपाय है तो बताओ। बाज ने कहा कि कबूतर के मांस के बराबर मुझे मांस दे दीजिए इससे मेरा काम हो जाएगा। राजा ने विचार किया कि एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव का कष्ट देना पाप होगा। यही सोच कर राजा ने कबूतर को तराजू के एक पलडे में डाल दिया और अपने शरीर से मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखने लगे। लेकिन काफी मांस रखने के बाद भी पलड़ा हिला तक नहीं। अंत में राजा शिव स्वयं दूसरे पलड़े पर बैठ गये और बाज से कहा कि तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। राजा के इस दयालुता और शरण में आये हुए कि मदद करने की भावना को देखकर कबूतर अग्नि देव और बाज देवराज इन्द्र के रूप में प्रकट हुए। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। देवराज इन्द्र ने कहा कि तुम ने धर्म की लाज रखी है। जो शरण में आये की रक्षा नहीं करता वह पापी है। कमजोर की सहायता न करने वाला भी अधर्मी है। दोनों देवताओं ने राजा शिवि को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग चले गये।

कार्टेल के खिलाफ जंग और मेक्सिको की अग्निपरीक्षा

सनत जैन

मेक्सिको में कुख्यात ड्रग सरगना नेमेंसियो ओसेगेरा सर्वांतेस उर्फ 'एल मेंचो' के मारे जाने की खबर के बाद हुई भारी हिंसा से मेक्सिको को अनिश्चितता के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। आम जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई है। नशे के कारोबार में (सीजेएनजी) प्रमुख के रूप में ड्रग लॉर्ड को न केवल मेंक्सिको, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का केंद्रीय चेहरा माना जाता था। मेक्सिको की सरकार इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। किंतु ड्रग सरगना के मारे जाने के तुरंत बाद भड़की आगजनी, हाईवे जाम और सुरक्षा कर्मियों पर हमले से यह सवाल उठता है, क्या किसी सरगना के मारे जाने पर जनता का विद्रोह इस रूप में देखने को मिल सकता है? एल मेंचो पर अमेंरिका की सरकार ने बड़ा इनाम घोषित किया था। डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल से ही मेक्सिको पर ड्रग तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दबाव अमेंरिका की सरकार बनाती रही है। फेंटानिल संकट ने अमेंरिका की आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया है, इसका प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ना तय है। मेक्सिको की हिंसा केवल आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका असर अमेंरिका सहित अन्य देशों पर भी पड़ना तय है। यह घटना भू-राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी दिखती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह मेक्सिको की संप्रभु रणनीति का हिस्सा है, या अमेंरिकी दबाव का परिणाम है। इतिहास बताता है कि कार्टेल के शीर्ष नेता को मार देने से इस समस्या का हल नहीं होता है। इससे ड्रग के कारोबार, राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों में स्थिरता संभव नहीं है। 2016 में जोक्विन एल चापो गुजमान की गिरफ्तारी के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आम जनता और सत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा था। संगठित अपराध का नेटवर्क समानांतर व्यवस्था की तरह संचालित होता है। एक चेहरा हटता है, तो उसके कई दावेदार उभरते हैं। गैंग में वर्चस्व की लड़ाई आम नागरिकों की सुरक्षा और जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है। एल मेंचो की मौत के बाद इस तरह की घटनाएं इसी आशंका को पुष्ट कर रही हैं। ड्रग कारोबार और राजनीतिक संरक्षण का मूल मेक्सिको, अमेंरिका एवं कई अन्य देशों तक फैला हुआ है। दशकों से मेक्सिको में फैली गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक संघर्ष, भ्रष्टाचार और कमजोर तथा भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था से जुड़ता है। मेक्सिको के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक पकड़ हमेंशा से कमजोर रही है। नशे के कारोबारी और इससे जुड़े हुए लोगों की समानांतर सत्ता चलती है। नशे के कारोबार में लगे अपराधी तत्व जिस तरह से काम करते हैं, उससे स्थानीय कारोबारियों को वसूली के डर से नियंत्रण और सीमापार तस्करी इनके साधन हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं हो सकती है। मेक्सिको सरकार के लिए यह दोहरी चुनौती है। एक ओर सरकार के ऊपर तत्काल कानून-व्यवस्था बहाल कर नागरिकों में भरोसा कायम करना है, दूसरी ओर दीर्घकालिक सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा।

मेक्सिको में न्यायिक पारदर्शिता, गवाहों की सुरक्षा, नशे की कारोबार में नेटवर्क पर वित्तीय प्रहार और पुलिस सुधार अनिवार्य है। सरकार, पुलिस और प्रशासन के बीच का भ्रष्टाचार रोकना, संस्थागत ढांचे को मजबूत नहीं किया तो यह 'जीत' अस्थायी साबित होगी। इसके साथ ही, इसका असर अमेंरिका में भी पड़ना तय है। अमेंरिका की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब तक अमेंरिका में नशीली दवाओं की मांग बनी रहेगी, आपूर्ति के नए रास्ते और नए गिरोह समय-समय पर उभरते रहेंगे। नशे का कारोबार केवल मेक्सिको की समस्या नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इससे निपटने के लिए साझा जिम्मेंदारी जरूरी है। दबाव की नीति के बजाय सहयोग, खुफिया साझेदारी और सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा। एल मेंचो का अंत प्रतीकात्मक जीत हो सकती है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यदि मेक्सिको में सुशासन और पारदर्शिता चाहिए तो भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामाजिक निवेश की ठोस रणनीति बनानी होगी। तभी नशे के कारोबार के गैंगस्टरों की छाया से मेक्सिको बाहर निकल पाएगा। इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करता है। नशे के कारोबार का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, इसमें भारी पैसा है। इस नेटवर्क को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से अभी कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के पश्चात जिस तरह के हालात मेक्सिको के बन गए हैं, उस चुनौती से निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेंरिका इस मामले में मेक्सिको की क्या मदद करता है, यह भी देखना होगा।

कचरे पर कड़ा रुख: न्यायपालिका के निर्देश और जमीनी सच्चाई

सुनील कुमार महला

ठोस कचरे का प्रबंधन आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि आज लगातार बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण, औधोगिकीकरण और उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण धरती पर ठोस कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, मानव व जीवों के स्वास्थ्य और विभिन्न संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यदि इस कचरे का सही तरीके से संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण(रि-साइक्लिंग) और इसका समय रहते निपटान नहीं किया गया, तो नीले ग्रह(धरती पर) पर भूमि, जल और वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है।

वास्तव में, आज के समय में ठोस कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करना, जैविक कचरे से खाद बनाना, प्लास्टिक और अन्य पदार्थों का पुनर्चक्रण(रि-साइक्लिंग) करना तथा जन-जागरूकता बढ़ाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब समाज और प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे, तभी सतत विकास(सस्टेनेबल डेवलपमेंट) और स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस क्रम में

हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के ठीक से पालन न होने पर चिंता जताई है और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि साफ और स्वस्थ पर्यावरण में जीना, जीवन के अधिकार का ही अहम् हिस्सा है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने 19 फरवरी को यह आदेश सुनाया। दरअसल, यह मामला भोपाल नगर निगम की उन अपीलों से जुड़ा था, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं।

अदालत ने यह बात कही है कि अभी कानून में सुधार का इंतजार करना ठीक नहीं है, क्योंकि कचरे की खराब व्यवस्था से लोगों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ता है। कोर्ट ने माना कि पूरे देश में कचरा प्रबंधन नियमों का पालन समान रूप से नहीं हो रहा है और घरों से गीला-सूखा-खतरनाक कचरा अलग-अलग करने की व्यवस्था अभी तक भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। बड़े शहरों में बढ़ते कचरे के ढेर भी चिंता का कारण हैं।कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा अब नहीं तो कभी नहीं और स्पष्ट किया कि अगर स्रोत पर कचरा अलग नहीं होगा और जरूरी सुविधाएं नहीं होंगी, तो अच्छे परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। अदालत ने पार्षदों, महापौरों और वार्ड प्रतिनिधियों को कचरा अलग कराने के लिए जिम्मेदार लीड फैसिलिटेटर बनाने को कहा, ताकि हर नागरिक नियमों का पालन करे। यहां पाठकों को बताता चलूं कि लीड फैसिलिटेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्यक्रम, प्रशिक्षण, कार्यशाला या परियोजना में पूरे समूह की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियाँ सही दिशा में और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार चलें। अच्छी बात यह है कि सभी नगर निकायों को 100% पालन के लिए समय-सीमा तय कर सार्वजनिक करने, प्रगति की फोटो जिलाधिकारी को भेजने और बड़े कचरा उत्पादकों से 31 मार्च तक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चार तरह के कचरे (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष) के अलग-अलग प्रबंधन की व्यवस्था जल्दी तैयार करने को कहा गया है।

अदालत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि कचरा प्रबंधन नियमों को स्कूल की पढ़ाई में शामिल किया जाए और इन्हें सभी राज्यों की स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए।अब नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले जुमार्ना, बार-बार उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है। लापरवाही करने वाले अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। कोर्ट ने मोबाइल अदालतों की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी न्यायालयों और संस्थानों में भी कचरा प्रबंधन नियमों का पालन होना चाहिए। नगर निकायों को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने होंगे, जैसे कचरा कम करना, घर में खाद बनाना और सैनिटरी कचरे को सुरक्षित तरीके से पैक करना।ये सभी निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि 1 अप्रैल 2026 से पहले पूरी तैयारी हो सके और नियम सही तरीके से लागू किए जा सकें।

अंत में यही कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही चिंता जताई है कि ठोस कचरा प्रबंधन केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। नियमों के कमजोर अनुपालन, स्थानीय निकायों की जवाबदेही की कमी और योजनाओं जैसे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा स्मार्ट सिटीज मिशन में खामियों के कारण समस्या बढ़ी है। समाधान के लिए सख्त नियम लागू करना, जनजागरण, अधिकारियों की जवाबदेही और बेहतर शहरी अवसंरचना निवेश अनिवार्य हैं, तभी कचरा-मुक्त भारत का लक्ष्य संभव हो पाएगा।

संक्षिप्त समाचार

कैलिफोर्निया हिमस्खलन में नौ स्कीयरों के शव बरामद

सिएरा, एजेंसी। कैलिफोर्निया की सिएरा नेवादा पर्वतमाला में आए भीषण हिमस्खलन के बाद बचाव दलों ने नौ बैककंट्री स्कीयरों के शव बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, हादसा लेक ताहो के पास कैसल पीक क्षेत्र में हुआ था। नेवादा काउंटी शेरिफ शैनन मून ने बताया कि कई एजेंसियों और 42 स्वयंसेवकों की मदद से अभियान पूरा किया गया। मृतकों में ब्लैबर्ज माउंटेन कंपनी के तीन गाइड, एंड्रयू अलिसांद्राटोस (34), निकोल चू (42) और माइकल हेनरी (30) शामिल हैं।

रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश, 11 ड्रोन मारे

मॉस्को, एजेंसी। रूस की राजधानी मॉस्को पर रविवार को ड्रोन हमले की कोशिश की गई। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक घंटे के भीतर 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इसके बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को के चारों अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। रूसी सिविल एविएशन एजेंसी ने बताया कि डोमोडेदोवो, व्नुकोवो, झुकोव्स्की और शेरेमेत्येवो एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं। अगली सूचना तक उड़ानों की आवाजाही रोकी गई है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि एयर डिफेंस ने मॉस्को की ओर बढ़ रहे एक और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। इसके साथ ही गिराए गए ड्रोन की कुल संख्या 11 हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लगभग चार साल पूरे होने वाले हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन उसके विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर राजधानी मॉस्को, पर ड्रोन हमले करता है। वहीं रूस भी यूक्रेन पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है।

जापान के सम्राट ने 3/11 आपदा पीड़ितों की पीड़ा पर जताई चिंता

टोक्यो, एजेंसी। जापान के सम्राट नारुहितो ने अपने 66वें जन्मदिन के अवसर पर 2011 के भूकंप, सुनामी और परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के जख्म अब तक नहीं भरने पर चिंता व्यक्त की। 11 मार्च की बरसी से कुछ सप्ताह पहले जारी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अभी अधूरी है। सम्राट नरुहितो ने पिछले सप्ताह दिए गए अपने संदेश में कहा, 'बुनियादी ढांचे की बहाली में प्रगति हुई है, लेकिन आजीविका और समुदायों के पुनर्निर्माण पर अभी भी काम किए जाने की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और जिनकी जीवन परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई, उनके बारे में सोचकर मुझे लगता है कि उनके घाव अब तक नहीं भरे हैं। समय बीतने के बावजूद वे दर्द आज भी कायम हैं।' जन्मदिन के अवसर पर सम्राट नरुहितो, महारानी मासाको, उनकी पुत्री राजकुमारी अइको और छोटे भाई क्राउन प्रिंस अकिशिनो के साथ शाही महल की बालकनी में आए और हाथ हिलाकर शुभकामनाएं देने पहुंचे नागरिकों का अभिवादन किया। लोग 'राइजिंग सन' के छोटे-छोटे झंडे लहराकर उनका स्वागत कर रहे थे। वर्ष 2011 की विनाशकारी आपदा में आए भीषण भूकंप और सुनामी से लगभग 20 हजार लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस आपदा के कारण फुकुशिमा दाइची परमाणु प्लांट में परमाणु रिएक्टर पिघलने (मेल्टडाउन) की घटना भी हुई थी। रेडिएशन के कारण खाली कराए गए अधिकांश इलाकों को दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन रोजगार और सामुदायिक ढांचे की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग अब तक वापस नहीं लौटे हैं।

नेपाल में तय समय पर ही होंगे आम चुनाव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले- चुनाव रोकने की खबर गलत

काठमांडो, एजेंसी। नेपाल के कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) रामप्रसाद भंडारी ने कहा कि आगामी चुनाव देश में सुशासन स्थापित करने और संविधान की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं। किसी भी स्थिति में मतदान प्रक्रिया नहीं रुकेगी।काठमांडो में रविवार को भंडारी ने कहा कि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद तरह-तरह की शंकाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं लेकिन इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में चुनाव का कोई विकल्प नहीं होता। कुछ असंतुष्ट तत्व चुनाव टलने की आशंका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नेपाली जनता ऐसे भ्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। भंडारी ने कहा कि पांच मार्च को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। उन्होंने कहा कि सुशासन की अपेक्षा रखने वाले नागरिकों को गुमराह कर अस्थिरता पैदा करने के प्रयास सफल नहीं होंगे। मीडिया से अपील करते हुए भंडारी ने मतदान से पहले मत सर्वेक्षण नहीं करने का आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव पूर्व ऐसे सर्वे मतदाताओं की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ता है।नेपाल में मधेश प्रांत की गौर नगरपालिका में सांप्रदायिक झड़पों के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात को देखते हुए कर्फ्यू बरकरार है।

नेपाल-बस हाईवे से नदी में गिरी, 18 की मौत

25 घायल, मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक, कंट्रोल खोने से हादसा

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के धादिंग जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि, यह किस देश से थे और इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं।

आर्म्ड पुलिस फोर्स के मुताबिक, अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाद में एक अन्य यात्री की मौत की पुष्टि हुई, जिससे मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया। हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू कर अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है।

बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी किसी कारण ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस त्रिशूली नदी में जा गिरी। हादसा देर रात करीब रात 1:30 बजे धादिंग जिले के बेनिघाट रोरांग इलाके में हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे की अन्य वजहों की भी जांच कर रही है।

हादसे के समय बस में 44 लोग सवार थे

मरने वालों में 12 पुरुषों और 6 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय बस में कुल 44 यात्री सवार थे। घायल 26 यात्रियों को बचा लिया गया है। कुछ का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि अधिकांश को आगे के इलाज के लिए काठमांडू रैफर कर दिया गया है। यह दुर्घटना आधी रात को होने के कारण बचाव अभियान में परेशानी हुई। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बचाव कार्य किया।

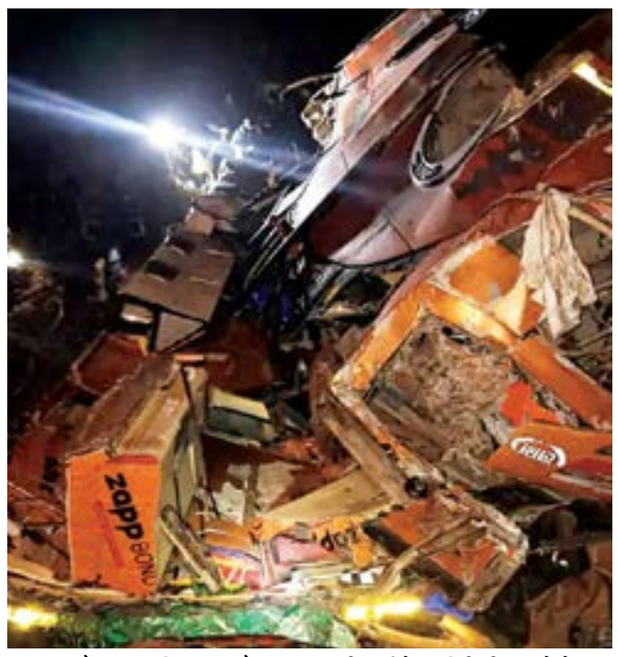

बारातियों से भरी बस खाई में गिरी थी

इससे पहले नेपाल के बैतड़ी जिले में 5 फरवरी को बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी। हादसे में 13 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए थे।

बस गांव से दुल्हन लेकर सुनकुड़ा जा रही थी। बस एक मोड़ पर चढ़ाई के दौरान अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हादसा ओवरलोडिंग के कारण हुआ था। वहीं, साल 2024 में लैंडस्लाइड की वजह से दो बसें त्रिशूली नदी में बह गईं थीं। दोनों बसों में चालकों समेत 63 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 7 भारतीयों और एक बस चालक की मौत हुई।

भगवान शिव के त्रिशूल से जुड़ी है त्रिशूली नही

त्रिशूली नदी नका नाम भगवान शिव के त्रिशूल से आया है। इसके पीछे एक प्रचलित कथा है कि गोसाइकुंडा (एक पवित्र जगह) में शिव जी ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा, जिससे तीन झरने निकले और ये नदी बनी। ये तिब्बत (चीन) के ग्यिरोंग काउंटी में शुरू होती है। वहाँ दो नदियाँ - क्यिरोंग त्सांगपो और लेंदे खोला से मिलकर त्रिशूली बनाती हैं। नेपाल में ये रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन जैसे जिलों से गुजरती है।

पृथ्वी हाईवे के साथ-साथ बहती है, जो काठमांडू और पोखरा को जोड़ता है। आखिर में ये नारायणी नदी (गंडकी नदी) में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। पुराने समय में ये काठमांडू वैली और तिब्बत के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता था। ये नदी स्थानीय लोगों के लिए पानी, सिंचाई, मछली पकड़ने और संस्कृति का हिस्सा है। पर्यटन (राफ्टिंग, ट्रेकिंग) से भी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है।

नदी के किनारे कई रिजॉर्ट्स, होटल और गांव हैं, जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। ये इलाका बौद्ध और हिंदू संस्कृति का मिश्रण है। हालांकि, मानसून में तेज बहाव, लैंडस्लाइड के कारण और यहां कई दुखद घटनाएँ हुई हैं।

मुझे अंधेरे में रखा; मुहम्मद यूनुस पर फायर हुए बांग्लादेश के राष्ट्रपति,

हालात बदलते ही बदले जज्बात

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म होते ही और आम चुनाव के बाद नई सरकार गठित होने ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के जज्बात भी बदल गए हैं। इतने दिनों से मोहम्मद यूनुस की अगुआई में चल रही बाग्लादेश की अंतरिम सरकार पर उन्होंने एक भी सवाल नहीं उठाया। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहे और भारत के साथ रिश्ते खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अब शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने उन्हें अंधेरे में रखा था।

राष्ट्रपति को अलग-थलग करने में जुटे थे यूनुस

बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने ना तो कभी संस्थानों के बीच समन्वय पर ध्यान दिया और ना ही वह किसी भी फैसले को लेकर उन्हें कोई जानकारी देते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि यहां तक कि विदेश दौरे की भी जानकारी उन्हें नहीं होती थी। विदेश नीति से संबंधित कोई भी सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचती ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अलग-थलग करने के लिए सारी राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे थे।

विदेश दौरे पर नहीं लेते थे सलाह

शहाबुद्दीन ने कहा कि सरकार को जरूरी फैसले राष्ट्रपति की सलाह से करने चाहिए लेकिन मोहम्मद यूनुस खुद ही सारे फैसले कर लेते थे। संविधान यह भी कहता है कि विदेश दौरे पर जाते समय राष्ट्रपति को जानकारी देनी चाहिए और लौटने के बाद इसके परिणामों पर चर्चा होनी चाहिए। कार्यकाल के दौरान वह 14 से 15 बार विदेश गए लेकिन एक बार भी उनकी सहमति नहीं ली गई।

राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा, अगर किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता होता है तो इसकी जानकारी राष्ट्रपति को होनी चाहिए लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। ना तो कभी मौखिक और ना ही लिखित रूप में कोई सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके बाद भी वह मुझे नजरअंदाज ही करते थे। वह मुझसे मिलने कभी आए ही नहीं, ऊपर से मुझे अंधेरे में रखते थे।

मैक्सिको में बढ़ती हिंसा के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों से घर में रहने की सलाह

मैक्सिको, एजेंसी। मैक्सिको में बढ़ती हिंसा और सुरक्षा अभियानों के बीच भारत के दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीयों से सतर्क रहने, भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने और फिलहाल घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है।

एल मेंचो की मौत से भड़की हिंसा : यह एडवाइजरी उस सैन्य कार्रवाई के बाद जारी की गई है, जिसमें मैक्सिको के सबसे कुख्यात ड्रग कार्टेल सरगना नेमेसियो ओसेगुएरा केरवेंटेस उर्फ एल मेंचो को मार गिराया गया। वे जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (ष्ह्वहत्न) का प्रमुख थे। मेंचो मैक्सिको व अमेरिका के मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों में शामिल थे। मैक्सिकन सेना ने पश्चिमी राज्य जलिस्को में एक ऑपरेशन के दौरान उन्हें ढेर किया।

अगली सूचना तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह : भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलिस्को राज्य (प्यूर्टो वल्लार्ता, चापाला और ग्वाडलाहारा), तामाउलिपास राज्य (रेनोसा सहित अन्य नगरपालिकाएं), मिचोआकान, गुएरेरो और नुएवो लियोन के कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा अभियान, सड़क अवरोध और आपराधिक गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। दूतावास ने नागरिकों को कानून-व्यवस्था से जुड़े अभियानों के आसपास के इलाकों से दूर रहने, स्थानीय मीडिया पर नजर रखने, अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। आपात स्थिति में 911 पर संपर्क करने की सलाह भी दी गई है। साथ ही भारतीयों से अपने परिवार और मित्रों को अपनी स्थिति की जानकारी नियमित रूप से देते रहने की सलाह दी गई है।

बेटी नहीं, पार्टी के शीर्ष पद पर चुने गए किम जोंग उन

प्योंगयाग, एजेंसी। तमाम अटकलों के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के शीर्ष पद पर फिर से निर्वाचित किया गया है। बीते कुछ समय से चर्चा चल रही थी कि किम जोंग उन अपनी बेटी को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को आंख दिखाते हुए देश में परमाणु हथियारों को और मजबूत करने का ऐलान किया है। गुरुवार से शुरू हुई पार्टी कांग्रेस में किम अगले पांच वर्षों के लिए अपने प्रमुख राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि वह परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने पर जोर देंगे। उत्तर कोरिया के पास पहले से ही ऐसी मिसाइल मौजूद हैं जो एशिया में अमेरिकी सहयोगियों और अमेरिकी मुख्य भूमि तक को निशाना बना सकती हैं।

हर पांच वर्ष में होते हैं चुनाव : विश्लेषकों का मानना है कि किम पारंपरिक सैन्य बलों को मजबूत करने और उन्हें परमाणु क्षमताओं के साथ एकीकृत करने के नए लक्ष्य घोषित कर सकते हैं। साथ ही वह चीन के साथ व्यापार में सुधार और रूस को हथियार निर्यात से मिली आर्थिक बढ़त के बीच ''आत्मनिर्भरता'' अभियान पर भी पुनः जोर दे सकते हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने बताया कि हजारों प्रतिनिधियों की ''एकमत इच्छा'' से किम को पार्टी का महासचिव चुना गया। वर्ष 2016 से हर पांच वर्ष में आयोजित इस कांग्रेस में शीर्ष नेता का चुनाव होता है।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया से तनाव : जानकारों का अनुमान है कि किम दक्षिण कोरिया के प्रति अपने कड़े रुख को और संस्थागत रूप दे सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2019 में वार्ता विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया का अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक संवाद ठप है। किम ने दक्षिण कोरिया को 2024 में स्थायी दुश्मन घोषित कर संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया था।

रूस से करीबी : किम जोंग उन यूक्रेन युद्ध में रूस का खुलकर साथ दे रहे हैं। उन ने हजारों सैनिकों को भी रूस की तरफ से युद्ध में उतारा है। वह रूस की यात्रा भी कर चुके हैं। जानकारों का कहना है कि रूस और उत्तर कोरिया मिलकर अपनी सेना को मजबूत करने और परमाणु हथियारों को बनाने पर जोर दे रहे हैं।

अटकलें थीं कि किम जोंग उन अपनी 16 साल की बेटी को पार्टी का महासचिव बना सकते हैं। बीते दिनों वह किम जोंग उनके साथ नजर आई थीं। हालांकि किम की बेटी किम जू ए अभी नाबालिग हैं। जानकारी के मुताबिक किम जू एक, किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू के तीन बच्चों में तीसरे नंबर पर हैं। वैसे तो किम जोंग उन अपने परिवार को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाते हैं लकिन उनकी बेटी कई बार उनके साथ दिख चुकी है। फरवरी में उनकी तस्वीरें डाक टिकट पर भी छपी थीं।

परमाणु कार्यक्रम पर जोर : विशेषज्ञों का मानना है कि किम अपनी परमाणु और मिसाइल नीति को और तेज करेंगे। उत्तर कोरिया पहले ही ऐसे मिसाइल विकसित कर चुका है जो एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों और अमेरिकी मुख्यभूमि तक पहुंच सकते हैं। पार्टी ने दावा किया कि परमाणु ताकत ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है और जनता का आत्मविश्वास बढ़ाया है।

ईरान के विश्वविद्यालयों में दूसरे दिन भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, अमेरिका से तनाव के बीच बिगड़े हालात

तेहरान, एजेंसी। ईरान के दो बड़े शहरों तेहरान और मशहद में विश्वविद्यालय परिसरों में लगातार दूसरे दिन सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। छात्र समूहों और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार कम से कम सात विश्वविद्यालयों में छात्र इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के बावजूद छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन जारी रखा। यह नया विरोध ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

बताया जा रहा है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही शनिवार से प्रदर्शन फिर तेज हुए। रविवार को कई छात्रों ने काले कपड़े पहनकर पहले हुए प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित कई संस्थानों में छात्रों की भीड़ देखी गई।

पहले भी हुआ था बड़ा दमन : जनवरी में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों ने सख्ती से दबा दिया था। अधिकार समूहों का दावा है कि हजारों लोग मारे गए और करीब 40 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी सरकार ने कहा था कि 3 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनके लिए उसने इस्राइल और अमेरिका समर्थित तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। उस समय प्रदर्शनकारियों ने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के शासन को समाप्त करने की मांग की थी।

सरकार की चेतावनी : हालिया प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार ने औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सरकारी मीडिया ने परिसरों में तनाव की खबरें दी हैं। तेहरान विश्वविद्यालय के एक अधिकारी हुसैन गोलदानसाज ने छात्रों को 'उग्र नारे' और हिंसा से दूर रहने की चेतावनी दी। सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है।

अमेरिका से बढ़ता तनाव : यह विरोध उस समय हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी है। ओमान की मध्यस्थता में दोनों देशों की वार्ता स्विट्जरलैंड में फिर शुरू होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि समाधान संभव है, लेकिन ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेगा। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ाई गई है।

ट्रम्प के रिजॉर्ट में घुस रहे युवक को गोली मारी, मौत

गन और फ्यूल केन लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मार-ए-लागो रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश करने वाले एक युवक को सुरक्षाकर्मियों ने गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना स्थानीय समयानुसार रविवार आधी रात 1:30 बजे हुई। राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली एजेंसी सीक्रेट सर्विस ने बताया कि युवक गैरकानूनी तरीके से सुरक्षित इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था। वह अपने साथ शॉटगन और फ्यूल केन लेकर आया था। मारे गए युवक की उम्र 20 साल थी, वह नॉर्थ कैरोलीना का रहने वाला था। फिलहाल उसकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले की जांच जारी है। घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रम्प वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में मौजूद थे। आमतौर पर वह वीकेंड पर मार-ए-लागो में समय बिताते हैं।

सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिजॉर्ट के नॉर्थ गेट से एक कार के बाहर निकल रही थी, इसी दौरान युवक ने अंदर घुसने की कोशिश की। उसके पास शॉटगन और फ्यूल केन थी। सीक्रेट सर्विस के दो एजेंट्स ने उसे रोका और उससे हथियार और केन गिराने को कहा गया। युवक ने केन तो रख दिया, लेकिन शॉटगन को गोली चलाने की पोजिशन में उठा लिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई और वह मारा गया। जांच में पता चला कि उसके परिवार ने कुछ दिन पहले उसे लापता होने की रिपोर्ट की थी। वह नॉर्थ कैरोलीना से साउथ की ओर आया था और रास्ते में शॉटगन खरीदा। उसकी कार में गन का डिब्बा मिला है। ट्रम्प की सुरक्षा में पहले भी चूक हो चुकी है। 13 जुलाई 2024 में ट्रम्प को एक रैली के दौरान एक हमलावर ने गोली मार दी थी। उस वक्त वे राष्ट्रपति नहीं थे। उन पर यह हमला राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 4 महीने पहले हुआ था।

20 साल के हमलावर ने 400 फीट की दूरी से ट्रम्प पर असॉल्ट राइफल से गोली चलाई थी। यह गोली उनके कान को छूते हुए गुजरी थी। इसके बाद ट्रम्प की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया था।

अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के पास होता है। यह एक फेडरल एजेंसी है, जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। सीक्रेट सर्विस की शुरुआत 1865 में हुई थी।

मेक्सिको में सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारा

ट्रम्प के दबाव के बाद एक्शन, देशभर में हिंसा शुरू, समर्थकों ने एयरपोर्ट-मॉल में आग लगाई

मेक्सिको सिटी, एजेंसी। मेक्सिको में सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो को मार गिराया। इसके बाद देशभर में आगजनी और हिंसा शुरू हो गई है। मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हाईवे को जाम कर दिया है और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन के दौरान वह घायल हो गया था। उसे एयरलिफ्ट कर मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में मेंचो के अलावा कम से कम और 9 अपराधी भी मारे गए हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एल मेंचो, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (ष्ह्वहत्न) का लीडर था। जलिस्को कार्टेल मेक्सिको में ड्रग्स बनाने और बेचने, स्थानीय कारोबारियों से वसूली करने और कई इलाकों में लोगों को डराकर रखने के लिए कुख्यात रहा है। इस कार्टेल की मौजूदगी अमेरिका के 50 राज्यों में है। अमेरिकी सरकार ने अल मेंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था।

पहले भी ऐसी हिंसक घटनाएं हुईं: मेक्सिको में पहले भी जब किसी बड़े कार्टेल नेता को पकड़ा गया या मारा गया है, तब सरकार और कार्टेल के बीच हिंसक टकराव हुआ है। कई बार गिरोह के अंदर ही सत्ता की लड़ाई छिड़ जाती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एल मेंचो की मौत से पहले 2016 में सिनाओला कार्टेल के सरगना एल चापो की गिरफ्तारी और 2024 में अल मायो की गिरफ्तारी के वक्त भी देश में ऐसा ही हुआ था। 2019 में जब अल चापो के बेटे ओविदियो गुजमान को पकड़ा गया था, तब उसके गुर्गों ने कुलियाकान शहर को घंटों तक बंधक बना लिया था और सरकार को उसे छोड़ना पड़ा था। इसलिए अब भी डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं।

अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जालिस्को कार्टेल के पास नया नेता साफ तौर पर तय है या नहीं। अगर अंदरूनी लड़ाई शुरू हुई तो खून-खराबा और बढ़ सकता है।

मेक्सिको पर एक्शन लेने को दबाव बना रहे थे ट्रम्प : जालिस्को कार्टेल कार्टेल 2009 में बना था। एल मेंचो की लीडरशिप में यह मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क बन गया था। यह कोकीन, मेथामफेटामिन और हाल के वर्षों में फेंटानिल जैसी सिंथेटिक ड्रग्स अमेरिका भेजता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेंचों की मौत से मेक्सिको और अमेरिका के रिश्तों में सुधार हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प मेक्सिको पर दबाव बना रहे थे कि वह कार्टेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वह सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं। इसी साल फरवरी में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्टेल को विदेशी टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन घोषित किया।मेक्सिको सरकार ने साफ कहा है कि अमेरिकी हमले से देश की संप्रभुता का उल्लंघन होगा, लेकिन खुफिया जानकारी के स्तर पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है।

टी20 विश्व कप के सुपर-8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करने उतरेगी श्रीलंका

कोलंबो (एजेंसी)। मेजबान श्रीलंकाई टीम बुधवार को अपने दूसरे सुपर-8 मैच में बुधवार को न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। श्रीलंकाई टीम को अपने पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब अगर वह न्यूजीलैंड से हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मेजबान श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज अपने पहले मैच में असफल रहे थे, ऐसे में उसे अगर कीवी टीम से जीतना है तो स्पिनरों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंकाई 147 रनों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाए थे। श्रीलंका की पिचें बल्लेबाजी के लिए कठिन मानी जाती हैं। इसके अलावा इन मैदानों पर बड़े शॉट खेलना भी कठिन होता है।

सुपर आठ के पहले मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाते दिखे थे और उसकी टीम को अपनी इन गलतियों से सबक लेना होगा। बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने टीम के खराब प्रदर्शन पर कहा, 'यह एक टी20 मैच है, इसलिए जाहिर है कि आप अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश करते हैं पर जब गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही होती है, तो कहना आसान है पर रन बनान कठिन है।'

पथुम निसांका ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है जबकि बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालेज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश से नहीं हो पाया था। जिससे दोनो को ही एक-एक अंक मिला है। कीवी टीम के पास भी कप्तान मिचेल सेंटनर सहित अच्छे स्पिनर हैं जो श्रीलंका के बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे।

दोनों टीम सुपर आठ में पहली जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और टिम सीफर्ट की जोड़ी ने लीग चरण के दौरान जबरदस्त बल्लेबाजी की है। इसके अलावा रचिन रविंद्र भी कनाडा के खिलाफ अर्धशतक लगाकर फॉर्म में आ गये हैं। ऐसे में श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए कीवी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना आसान नहीं रहेगा।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंदु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, ईशान मलिंगा।

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, इश सोढ़ी, कोल मैकॉन्ची।

अभिषेक, तिलक और रिंकू पर लटक रही तलवार

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच टेन डोइशे और सितांशु का कहना है सुपर-8 के अगले मैचों के लिए टीम की फिर से समीक्षा करते हुए बदलाव किये जायेंगे। ऐसे में तय है कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की जगह खतरे में हैं। इन तीनो में से किसी एक का बाहर जाना तय है। ये तीनो ही अब तक इस टूर्नामेंट में असफल रहे हैं। इसके अलावा टीम प्रबंधन शीर्ष क्रम में अधिक बाएं हाथ के बल्लेबाजों को उतारे जाने की रणनीति पर भी फिर विचार करेगा। दक्षिण अफ्रीका से पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम की हार के बाद से ही उसके लिए अब बचे हुए दोनो मैच बड़े अंतर से जीतना जरुरी है। इसलिए फार्म से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को बनाये रखने का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। अभिषेक अब तक चार मैचों में 15 रन जबकि तिलक वर्मा पांच मैचों में 107 रन ही बना पाये हैं। इसके अलावा रिंकू भी फिनिशर की भूमिका में विफल रहे हैं। वह 29 गेंदों में 82.75 की स्ट्राइक रेट से केवल 24 रन ही बना पाये हैं।

कोटक ने कहा, अगर मुख्य कोच और टीम प्रबंधन को लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने हैं तो हम करेंगे। अब इस पर विचार हो रहा है कि अगर हमें बदलाव करना है तो वह क्या होगा और कैसे होगा। अब हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं कि हमें कुछ भी बादलाव करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। वहीं डोइशे ने माना है कि टीम में बैकअप में विशेषज्ञ बल्लेबाजों की की है। उन्होंने कहा, या तो आप उन्हीं खिलाड़ियों को चुनते हैं जो आपको लगता है कि पिछले डेढ साल में अच्छा खेल रहे हैं, भले ही अभी रन नहीं बना पा रहे हैं। या फिर बदलाव करके संजू सैमसन को लाते हैं जो शानदार खिलाड़ी है और उनके आने से शीर्षक्रम में दायें और बाएं का संयोजन लाभकारी रहेगा। उन्होंने कहा, अगले दो अहम मैचों से पहले सैमसन को शामिल करने के बारे में विचार होगा। साथ ही कहा कि अभिषेक और तिलक का फॉर्म चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ये दोनो ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाये हैं। वहीं अभिषेक को सलाह दिये जाने को लेकर कोटक ने कहा, बल्लेबाजी कोच होने के कारण मेरा मानना है कि उसे जरूरत से ज्यादा सलाह देने की जरुरत नहीं है। उसके दिमाग को ठीक से काम करने दें। लगातार सलाह से मानसिक दबाव पड़ता है जिससे बल्लेबाज का मनोबल गिरता है। उसे अपने अनुसार खेलने देना ही बेहतर रहेगा

तिलक अंतिम ग्यारह में शामिल करने के लायक नहीं : श्रीकांत

-सैमसन को मिले अवसर

चेन्नई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत ने कहा है कि तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे। इसलिए अंतिम ग्यारह में उनकी जगह नहीं बनती है। श्रीकांत के अनुसार अभी के समय में तिलक को टीम में रखना फायदेमंद नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी वह केवल एक रन बनाकर पेवेलियन लौट गये। इससे अन्य बल्लेबाजों पर दबाव आ गया था। उन्हें ऐसे समय पर अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिये थी। , क्योंकि ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए थे।

अब तक विश्वकप के पांच मैचों में तिलक 118.88 के स्ट्राइक रेट से 107 रन बना पाये हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिलक के आउट होने के तरीके से श्रीकांत नाराज हैं। उनका कहना है कि अब सुपर-8 के बचे हुए मैचों में संजू सैमसन को उनकी जगह शामिली किया जाना चाहिये। श्रीकांत ने कहा, ÷अगर सैमसन को 11 में आना है, तो तिलक के लिए कोई जगह नहीं है। कई अनय लोग भी तिलक के बल्लेबाजी के तरीके से हैरान हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो शॉट खेला, उसके लिए उन्हें 11 से बाहर किए जाने की पूरी संभावना है। यह काफी खराब शॉट था और ऐसा शॉट खेलने के बाद वह क्रीज पर टिके रहने के लायक नहीं थे।÷

श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली के संन्यास के बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम मुश्किल में आ जाती है।

ब्रिस्बेन वनडे में टीम इंडिया की करारी हार, स्मृति मंधाना का अर्धशतक गया बेकार

ब्रिस्बेन (एजेंसी)। मंगलवार को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेले गए वनडे द्विपक्षीय श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत को छह विकेट से हरा दिया। एलिसा हीली की अगुवाई वाली टीम ने तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में 1-2 से हार के बाद इस मैच में उतरी थी। उन्होंने मेहमान टीम को 214 रनों पर रोककर 215 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए, कप्तान हीली ने फोएबे लिचफील्ड (32 गेंदों में 32 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की। श्री चरानी ने 11वें ओवर में अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने इसी ओवर में जॉर्जिया वोल को भी आउट किया। आउट होने वाली कप्तान हीली ने 70 गेंदों में 50 रन बनाए। उन्होंने बेथ मूनी (79 गेंदों में 76 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी की। एनाबेल सदरलैंड (44 गेंदों पर 48 रन नाबाद) और गार्डनर (4 गेंदों पर 5 रन नाबाद) नाबाद रहीं और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत हासिल कर ली। मैच जिताने वाली इस शानदार पारी के लिए मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनते हुए, भारतीय महिला टीम ने पहले ही ओवर में अपना पहला विकेट खो दिया जब मेगन शट ने विकेट के सामने प्रतिका रावल को कैच दे दिया। शेफाली वर्मा एक रन पीछे बल्लेबाजी करने आईं और लय हासिल नहीं कर सकीं। उन्होंने 17 गेंदों में सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। डार्सी ब्राउन ने उन्हें आठवें ओवर में कैच आउट किया। जेमिमा रोड्रिग्स भी सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गईं। पावरप्ले खत्म होने के तुरंत बाद एशले गार्डनर ने उन्हें आउट कर दिया। बेथ मूनी ने विकेट के पीछे एक शानदार कैच पकड़ा।

स्मृति मंधाना ने 20वें ओवर में ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। मैकग्राथ ने अपने अगले ओवर में मंधाना को 58 रन पर आउट कर दिया। उन्होंने अपनी प्रभावशाली पारी में सात चौके लगाए। दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं और जल्द ही सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इसके बाद ऋचा घोष कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ शामिल हुईं और दोनों ने छठे विकेट के लिए 37 रन जोड़े।

आईपीएल की तरह बदलाव वाली नीति विश्वकप में नहीं चलती : अश्विन

नई दिल्ली । भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने टीम प्रबंधन की रणनीति पर सवाल उठाये हैं। अश्विन के अनुसार टी20 विश्वकप जीतने के लिए टीम प्रबंधन को आईपीएल वाली बदलाव की सोच से बाहर आना होगा। अश्विन ने कहा कि प्रबंधन ने जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर बिठाया वह समझ से परे हैं। साथ ही कहा कि ये सब आईपीएल में चलता पर विश्वकप में नहीं। अश्विन ने कहा कि इस प्रकार के बदलाव आईपील में इसलिए चलते हैं क्योंकि टीम को 14 गेम खेलने होते हैं पर आईसीसी टूर्नामेंट में बदलाव कम से कम होने चाहिये और जितना आज टीम को स्थर रखते हैं उतना ही लाभ होता है। अश्विन ने साथ ही कहा, आपको नहीं भूलना चाहिए कि अक्षर ने पिछले विश्व कप में किस प्रकार का प्रदर्शन किय था।

धोनी ऐसी बाइक चलाते दिखे जो भारत में लांच ही नहीं हुई थी

रांची । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बाइक ?स के काफी शौकीन हैं। रांची की सड़कों पर भी वह कई बार बाइक चलाते दिखते हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक बाइकें हैं। जिसमें डुकाटी, कावासाकी, हार्ले-डेविडसन, यामाहा के अलावा कई विंटेज और हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स भी हैं। वहीं अब धोनी एक वीडियो में

ऐसी बाइक चलाते दिखें हैं जो भारत में कभी लांच ही नहीं हुई थी। ये यामहा की एसआर400 है। यह पुराने जमाने की ऐसी बाइक है जो भारत में कुछ ही लोगों के पास हैं। ये क्लासिक रेट्रो-स्टाइल मोटरसाइकिल साल 1970 की यूनिवर्सल जापानी मोटरसाइकिल्स से प्रेरित होकर 1978 में बनायी गयी थी पर 2021 में इसे बनाना बंद कर दिया गया। इसका कारण है कि यह पुरानी टेक्नोलॉजी वाली बाइक थी और प्रदूषण के नये मानकों पर खरी नहीं उतरी। यह बाइक कस्टमाइज़ेशन के कारण काफी लोकप्रिय हुई है। इससे भारत में कभी भी आधिकारिक रुप से लांच नहीं किया गया केवल ये आयात की गयी है। ये एक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि दोपहिया वाहनों की दुनिया में एक 'टाइम मशीन' की तरह है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 399सीसी का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजन है। इस बाइक की ट्यूनिंग इस तरह की गई है कि यह कम रफ्तार पर भी काफी अच्छी चलती है।इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट का विकल्प भी नहीं है और किक से स?टार्ट होती है। ये ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी काफी अच्छे से चलती है। इसमें सिग्नेचर टीयरड्रॉप फ्यूल टैंक, गोल हेडलाइट और चमकता हुआ क्रोम एग्ज़ॉस्ट दिया गया है। ये बाइक 130-140 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक जा सकती है।

गंभीर की पॉलिटिक्स ने टीम इंडिया की इमेज को नुकसान पहुंचाया, पूर्व पाक बल्लेबाज का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने टीम इंडिया के हेडकोच गौतम गंभीर पर तीखी टिप्पणी की है। शहजाद का दावा है कि गंभीर की राजनीतिक पृष्ठभूमि का असर टीम के माहौल पर पड़ा है। साथ ही उन्होंने चयन फैसलों और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

सुपर 8 हार के बाद बढ़ा दबाव

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली बड़ी हार ने भारतीय खेमे में चिंता बढ़ा दी है। इस हार के बाद सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है, जिससे कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट पर दबाव साफ दिख रहा है। कुछ चयन फैसलों ने भी बहस को जन्म दिया। अहम मुकाबले में अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका देने पर फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों ने सवाल उठाए।

पॉलिटिक्स टीम में भी आ गई : शहजाद

अहमद शहजाद ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान गंभीर का दृष्टिकोण बदल गया। उनका इशारा उस समय की ओर था जब गंभीर सांसद रहे। शहजाद का मानना है कि राजनीति का असर अब टीम प्रबंधन में भी दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, किसी भी खेल में सफलता के लिए पूर्ण फोकस जरूरी होता है, और अगर ध्यान बंटे तो उसका असर टीम के माहौल पर पड़ सकता है।

कुलदीप यादव को लेकर उठे सवाल

शहजाद ने यह भी कहा कि टीम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कुलदीप यादव का जिक्र किया, जिन्हें टूर्नामेंट में सीमित मौके मिले हैं। उनका कहना था कि कुलदीप जैसे मैच-विनर स्पिनर को लगातार बाहर रखना समझ से परे है। टी20 फॉर्मेट में विविधता और विकेट लेने की क्षमता बेहद अहम होती है, और कुलदीप उस भूमिका को निभा सकते हैं।

कप्तान के साथ विवाद की चर्चा

शहजाद ने एक कथित घटना का भी जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और कुलदीप के बीच कहासुनी की बात सामने आई थी। हालांकि बाद में दोनों खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी अनबन से इनकार किया। फिर भी शहजाद का मानना है कि कुलदीप को बाहर रखने के पीछे कोई और कारण हो सकता है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

चयन और रणनीति पर बहस

टीम इंडिया के चयन और रणनीति को लेकर चर्चा तेज है। आलोचकों का कहना है कि बड़े टूर्नामेंट में टीम कॉम्बिनेशन का संतुलन बेहद अहम होता है। स्पिन विकल्पों और ऑलराउंडर्स के बीच सही तालमेल बनाना जीत की कुंजी साबित हो सकता है। इसके बावजूद यह भी तथ्य है कि गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार की अगुवाई में भारत ने हालिया बाइलेटरल सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है।

एफआई प्रो लीग में स्पेन ने भारतीय हॉकी टीम को हराया

होबार्ट । स्पेन ने एफआई एच प्रो लीग के ऑस्ट्रेलियाई चरण में भारतीय हॉकी टीम को शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। दोनो टीमों के बीच तय समय तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा पर इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपना पर गोल नहीं कर पायीं। 19वें मिनट में कप्तान हार्दिक सिंह के एक पास पर मनिंदर सिंह ने गोल दागकर भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने जबरदस्त प्रहार किये पर भारतीय रक्षा पंक्ति और गोलकीपर ने बचाव कर लिया। इसके बाद भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले किये। स्पेन के ब्रूनो फॉन्ट ने अंतिम क्षणों में शानदार गोल दागकर मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। वहीं इसके बाद हुए शूटआउट में भारत के अभिषेक और हार्दिक सिंह गोल नहीं कर पाये जिससे स्पेन ने 4-3 से मुकाबला जीत लिया।

बीसीएल में खेलते नजर आयेंगे धवन

मुम्बई। हाल में आयरलैंड की सोफी शाइन से दूसरी शादी करने वाले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अब बिग क्रिकेट लीग (बीसीएल) के दूसरे सत्र में खेलते नजर आएंगे। धवन बीसएल के दूसरे सत्र में 'यूपी ब्रिज स्टार्स' की ओर से खेलेंगे। धवन जैसे अनुभवी क्रिकेटर का लाभ टीम के युवाओं को मिलेगा। इससे पहले इसे लीग के पहले सत्र में भी धवन ने अच्छा प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया था। बिग क्रिकेट लीग का आयोजन ग्रेटर नोएडा के खेल परिसर में होगा। ये टूर्नामेंट 11 मार्च से शुरु होगा और इसका खिताबी मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा। यूपी ब्रिज स्टार्स प्रबंधन को उम्मीद है कि धवन की कप्तानी में टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगी। उनके रहने से से युवा खिलाड़ियों को भी सीखने का काफी अवसर मिलेगा ।बीसएल एक ऐसा टूर्नामेंट हैं जिसमें गली-मोहल्लों में खेलने वाले प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सितारों के साथ खेलने का अवसर मिलता है। इस लीग में डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, वकील, किसान या किसी भी अन्य पेशे से जुड़ा व्यक्ति खेल सकता है। खास बात ये है कि आम खिलाड़ियों को भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिलता है।

जब हम वेस्टइंडीज से खेलेंगे तो नेट रन-रेट जरूर मायने रखेगा : पार्थिव पटेल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मैच में अहमदाबाद में 76 रन से हार का सामना करना पड़ा। जियोस्टार के 'फॉलो द ब्लूज' पर बात करते हुए, जियोस्टार एक्सपर्ट पार्थिव पटेल ने भारत की हार, पावरप्ले में उनकी बैटिंग को लेकर चिंताओं और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच के लिए प्लेइंग ढ्ढ में संभावित बदलावों का विश्लेषण किया।

पार्थिव पटेल ने भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की जीत पर कहा, '12 मैचों की जीत का सिलसिला पक्का खत्म हो गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने बेहतर क्रिकेट खेला। मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान बनाया था और अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हालांकि, हार का मार्जिन काफी है, और नेट रन-रेट निश्चित रूप से तब काम आएगा जब हम 1 मार्च को कोलकाता में वेस्ट इंडीज का सामना करने जाएंगे। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ी जीत है, और यह सभी मुश्किलों के बावजूद मिली, यह देखते हुए कि इंडियन टीम जिस तरह से खेल रही थी। आपको दक्षिण अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा। हां, उन्हें कुछ समय के लिए अहमदाबाद में खेलने का फायदा मिला, लेकिन यह हमारा घर है। जाहिर है, भारतीय टीम वापस जाकर यह देखना चाहेगी कि क्या उन्होंने चीजों को सिंपल रखने के बजाय उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था।'

पावरप्ले में भारत को जरूरी शुरुआत नहीं मिलने पर पार्थिव पटेल ने कहा, 'सिर्फ इस गेम में ही नहीं, बल्कि नामीबिया या अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भी, हालांकि वह बैटिंग के लिए मुश्किल विकेट था, लेकिन जल्दी विकेट खोना भारत के लिए चिंता की बात रही है। जिस तरह से भारत ने पावरप्ले में विकेट खोए हैं, खासकर ऑफ-स्पिनरों के खिलाफ, वह चिंता की बात है। इस बार यह मार्करम के लिए था। वे बहुत ज़्यादा शॉट खेल रहे हैं, एंगल के खिलाफ जा रहे हैं। शायद वे बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं, खासकर टॉप पर तीन लेफ़्ट-हैंडर होने पर। वे सूर्यकुमार को नंबर तीन पर भेज सकते थे। मुझे लगा कि भारत इस गेम में ऐसा कर सकता था। जब आप हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड वाला गेम खेलते हैं, तो ऐसे दिन आना तय है।'

पटेल ने संजू सैमसन की प्लेइंग ड्ढ में वापसी पर कहा, 'मैं अक्षर पटेल को टीम में वापस आते देखना चाहूंगा। उन्होंने पहले भी अहम पारियां खेली हैं। हां, मैच-अप की भी अहमियत है, लेकिन मैं अक्षर पटेल को जरूर लाऊंगा। संजू सैमसन का भी सवाल है। चेन्नई में अब उनकी घर वापसी भी हो सकती है। यह कुछ ऐसा है जिस पर भारत जरूर विचार करेगा, खासकर यह देखते हुए कि भारतीय लेफ्ट-हैंडर ऑफ-स्पिनर के खिलाफ बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। जब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, तो सिकंदर रजा भी पावरप्ले में काम आ सकते हैं। मैं तिलक की जगह संजू सैमसन को नहीं उतारूंगा। हां, संजू सैमसन भी अच्छे फॉर्म में नहीं हैं। या शायद, भारत बैटिंग ऑर्डर बदलने की कोशिश कर सकता है, फिर सूर्या को नंबर तीन पर बैटिंग करनी होगी।'

इंडो-हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी प्रियामणि

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाया है। साथ ही बाकी भारतीय कलाकारों के लिए भी राह खोली है। प्रियंका की राह पर चलते हुए साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि भी अब एक इंडो-हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही हैं। इसमें उनके साथ टीवी पर 'महादेव' का किरदार निभाने वाला एक चर्चित एक्टर नजर आएगा।

मोहित रैना होंगे प्रियामणि के अपोजिट

इस फिल्म में प्रियामण के अपोजिट टीवी के चर्चित एक्टर मोहित रैना नजर आएंगे। वह बॉलीवुड फिल्मों और सीरीज में भी दमदार किरदार निभा चुके हैं। लेकिन टीवी सीरियल 'देवों के देव महादेव' में उन्होंने भगवान शिव की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का हिस्सा बनने पर मोहित रैना कहते हैं, 'यह प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि यह पहचान और अपनेपन को बहुत ईमानदारी से दिखाता है।' वहीं प्रियामणि ने कहा, 'जिस चीज ने मुझे तुरंत इस फिल्म की तरफ खींचा, वह थी कहानी का इमोशन और सच्चाई।' यूएस बेस्ड रेड बाइसन प्रोडक्शंस ने इस क्रॉस बॉर्डर फीचर फिल्म के लिए मुंबई के एज्योर एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। यह फिल्म हर्ष महादेश्वर द्वारा लिखी गई। वही इसका डायरेक्ट करेंगे। अभी तक फिल्म का टाइटल नहीं रखा गया है। यह एक फीचर फिल्म होगी, जिसकी कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें एक अप्रवासी परिवार की भावुक कहानी दिखाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट अप्रैल 2026 में शुरू होगा।

अब 'प्रोड्यूसर' बन लोगों का दिल जीतेंगी नित्या मेनन

अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज करने वाली साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री नित्या मेनन अब नई शुरुआत करने जा रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि वे अब बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू करने जा रही हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने नए प्रोडक्शन हाउस का ऐलान किया। अभिनेत्री नित्या मेनन ने लिखा, 'मेरे लिए फिल्में बनाना सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि दिल से दिल जुड़ने का तरीका है। जब मैं कुछ बनाती हूं तो यह न सिर्फ दर्शकों को बदलता है, बल्कि मुझे भी बदल देता है।' अभिनेत्री ने बताया कि रचनात्मक प्रक्रिया में डूबकर मैं खुद में बदलाव महसूस करती हूं और जो इसे देखते हैं, उनके अंदर भी एक हल्का-सा परिवर्तन आता है। अभिनेत्री ने लिखा, 'यह बदलाव शुरू में शायद नजर न आए, लेकिन यह हमेशा के लिए असर छोड़ जाता है। फिल्म बनाना मेरे लिए व्यक्तित्व के उस सच्चे और संवेदनशील हिस्से को छूने जैसा है, जो सबसे असली होता है, जब मैं अभिनय करती थी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगी और अब प्रोडयूस करने पर भी यही सोच बनी रहेगी। आपके सामने पेश है- कीयूरी प्रोडक्शंस।' वीडियो में बताया गया है कि केयुरी धरती की गुफाओं से निकली है, चट्टान से बनी है, रोशनी से प्यार करती है, और किसी खास रूप में नहीं बंधी है। यह नाम और उसका मतलब नित्या की रचनात्मक सोच को दर्शाता है, जहां वे ऐसी कहानियां बनाना चाहती हैं जो गहरी भावनाओं को छूएं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।

नित्या मेनन साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। वे अभिनेत्री होने के साथ-साथ पार्श्व गायिका भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 'थिरुचित्राम्बलम' (2022) के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और चार फिल्मफेयर अवार्ड साउथ मिल चुके हैं। साल 1998 में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली नित्या मेनन बॉलीवुड की फिल्म 'मिशन मंगल' में नजर आई थीं।

युवराज सिंह की बायोपिक करना चाहते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी

अपनी आगामी फिल्म ' दो दीवाने सहर में' को लेकर चर्चा में बने अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक बार फिर अपने उस ड्रीम रोल के बारे में खुलकर बात की है, जो सालों से उनके दिल के बेहद करीब है। जी हाँ, अपने करियर की शुरुआत क्रिकेट पर आधारित वेब सीरीज 'इनसाइड एज' से करनेवाले सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक बार फिर क्रिकेट की तरफ लौटते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक करने की इच्छा जताई है। गौरतलब है कि अमेजॉन प्राइम विडिओ के वेब सीरीज 'इनसाइड एज' में क्रिकेट की चमक-दमक के पीछे की अंधेरी दुनिया को सिद्धांत ने बखूबी उकेरा था। फिलहाल बायोपिक के संदर्भ में सिद्धांत कहते हैं, 'मैं वर्ष 2019 से कहता आ रहा हूं और आज भी कहूंगा और कहूंगा, बल्कि इसे मैनिफेस्टभी करता हूँ एक दिन मुझे मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक करने का मौक़ा मिले। उनकी जर्नी एक रोलरकोस्टर की तरह वाकई अविश्वसनीय रही है। मुझे वे न सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर पसंद हैं, बल्कि व्यक्तित्व भी उनका शानदार है। मैं उनके क्रिकेट के साथ उनकी लाइफस्टाइल, और समस्याओं के प्रति उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, जिस तरह उन्होंने परेशानियों को मात दी। वाकई वे एक आइकन हैं, और दुनिया को उनकी कहानी जरूर जाननी चाहिए।' वैसे बायोपिक की बात करें तो सिद्धांत जल्द ही दिग्गज फिल्ममेकर 'वी. शांताराम' का चुनौतीपूर्ण बायोपिक में नज़र आनेवाले हैं और इसके फर्स्ट लुक के साथ ही वे अपने दर्शकों की सराहना भी पा चुके हैं।

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' से बचकर निकले सनी देओल; आगे खिसकी 'गबरू' की रिलीज डेट

सनी देओल अभिनीत फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस्त तरीके से सफल हुई है। इस बीच वे अपने आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं, जिनमें फिल्म 'गबरू' का भी नाम है। पहले यह फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी। मगर, अब दर्शकों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रिलीज डेट में बदलाव किया गया है।

'गबरू' कब होगी रिलीज?

'बॉर्डर 2' के बाद सनी देओल के फैंस की नजर उनकी आगामी फिल्मों पर टिकी है। शशांक उदयपुरकर निर्देशित यह फिल्म पहले 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। मगर, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह फिल्म 08 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हाल ही में हड्ड के साथ बातचीत में सनी देओल ने 'गबरू' को अपने दिल के सबसे करीब फिल्मों में से एक बताया।

फिल्म 'चांद मेरा दिल' से होगा टकराव

फिल्म 'गबरू' को विशाल राणा और ओम छंगानी के प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सनी देओल के साथ सिमरन और प्रीत कमानी अहम रोल में हैं। सनी देओल की 'गबरू' की रिलीज डेट में बदलाव के बाद अब इसका मुकाबला लक्ष्य ललवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' से होगा। यह फिल्म भी 08 मई को रिलीज होने वाली है। अनन्या और लक्ष्य की फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है।

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' से बच निकले सनी देओल

बता दें कि मार्च में दो बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश की 'टॉक्सिक'। दोनों ही फिल्में 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही हैं। 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस्त तरीके से सफल रही। इसके दूसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ, 'टॉक्सिक' का भी क्रेज है। संभवतः इन दोनों फिल्मों से भिड़ंत से बचने के लिए मेकर्स ने सनी देओल की 'गबरू' की रिलीज में बदलाव किया है।

'द वॉर्डरोब' से होगा दिव्या अग्रवाल का बॉलीवुड डेब्यू

अपकमिंग बॉलीवुड हॉरर फिल्म 'द वॉर्डरोब' का फर्स्ट-लुक पोस्टर आ गया है। टीवी रियलिटी शोज की विजेता रह चुकीं दिव्या अग्रवाल इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं।

पोस्टर में एक पुरानी, आधी खुली लकड़ी की अलमारी से एक रहस्यमयी महिला बाहर आती दिखाई दे रही है। अलमारी के अंदर से निकलती लाल रोशनी उसके खून से सने सफेद गाउन को और डरावना बना रही है। चारों ओर धुआं, गहरे साए और खौफ का माहौल, पूरा सीन किसी डरावने सपने जैसा लगता है। लाल रंग में लिखा फिल्म का टाइटल 'द वॉर्डरोब' अंधेरे बैकग्राउंड पर और भी डरावना एहसास दे रहा है। दिव्या ने कहा, 'इस फिल्म ने मुझे एक कलाकार के तौर पर चैलेंज किया। कहानी बहुत ग्रिपिंग और एटमॉस्फेरिक है। मैं चाहती हूं कि दर्शक इसे जल्द से जल्द देखें।' वहीं रजनीश दुग्गल ने भी फिल्म की स्क्रिप्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें सस्पेंस और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का शानदार बेलेंस है।

फिल्म की कहानी एक साधारण-सी दिखने वाली अलमारी से शुरू होती है, जो धीरे-धीरे डरावनी घटनाओं की एक लंबी कड़ी को जन्म देती है। ट्विस्ट, शॉक और रहस्य से भरी यह कहानी दर्शकों को सीट से बांधे रखने पर मजबूर कर सकती है। फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म बनाने के लिए प्रियंका ने किया प्रेरित

मीरा चोपड़ा साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अलावा प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन के तौर पर पहचानी जाती हैं। शादी के बाद वह फिल्मों से दूर थीं लेकिन अब बतौर फिल्ममेकर उन्होंने साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' के साथ वापसी की। हमसे खास बातचीत में उन्होंने अपने करियर, प्रियंका चोपड़ा की सलाह सहित कई विषयों पर बात की।

बतौर फिल्ममेकर डेब्यू करने के बाद क्या वह आगे अपनी फिल्म में बहन प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने के बारे में सोचती हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने हंसते हुए कहा, 'नहीं...नहीं। अभी तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं अभी उनको एफोर्ड ही नहीं कर सकती हूं। मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचती हूं। हां जब बड़ी फिल्ममेकर बन जाऊंगी तो एक दिन अपनी फिल्म में प्रियंका को कास्ट करना चाहूंगी।'

बिजनेस में हाथ आजमाने के मीरा के फैसले पर बहन प्रियंका चोपड़ा का क्या रिएक्शन था? इस बारे में वह बताती हैं, 'मैंने सीधे उन्हें अपनी फिल्म (गांधी टॉक्स) का टीजर भेजा। मैंने उनको बताया कि ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है। उनको इस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। प्रियंका का व्यवहार कुछ ऐसा है कि हम में से कोई जब कुछ अच्छा करता है, तो वह बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। प्रियंका ने मुझे कहा था कि फिल्म बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, आपने टीजर बना दिया है तो प्लीज अब फिल्म बनाओ। दरअसल, उन्होंने इस इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड में जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, वो ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। जब आपके परिवार में ऐसा कोई होता है तो आप उससे प्रेरित होते हैं। आप पहले उसको देखते हैं। हमेशा एक चाह थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि प्रियंका कहे कि मुझे तुम पर गर्व है और उन्होंने ऐसा कहा, ये मेरे लिए ये बड़ी है।

एक्टिंग में लगातार काम नहीं मिलता

एक इंटरव्यू में मीरा ने कहा था कि वह स्क्रीन पर वापसी के लिए लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन अब वह बतौर फिल्ममेकर वापसी कर रही हैं। क्या शादी के बाद एक्टिंग में लौटना उनके लिए चुनौती भरा फैसला है? इस पर वह कहती हैं, 'मेरे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं आई। लेकिन एक्टिंग में क्या है कि आपको दो साल काम नहीं मिला तो आप काम नहीं करोगे, फिर एकदम से एक ही साल में दो प्रोजेक्ट आ जाएं तो आप काम करोगे। दरअसल, एक्टिंग ऐसा पेशा नहीं है कि लगातार आपको काम दे ही देगा। मैं ऐसा प्रोफेशन चाहती थी कि आपका लगातार काम चलता रहे, इसलिए मैंने प्रोडक्शन का काम शुरू किया। वो मेरे कंट्रोल में है कि मुझे कब क्या बनाना है, क्या करना है।

एक्टिंग में तो जब प्रोजेक्ट मिलेगा, जब आपको कुछ अच्छा लगेगा तब आप कर पाओगे। मैंने तीन साल काम करने के बाद फिर सोचा कि अब एक्टिंग में वापसी करूंगी और बहुत जल्द मैं आपको स्क्रीन पर दिखूंगी। एक्टिंग मेरा प्यार है, मैं जिंदगी में चाहे कुछ भी करूं, एक्टिंग नहीं छोड़ूंगी।'

फिल्म के गाने बनाने में समय लग गया

साइलेंट फिल्म के साथ बतौर प्रोड्यूसर वापसी करना और फिल्म की स्क्रीनिंग के लंबे समय बाद रिलीज करना कितनी बड़ी चुनौती थी? इस बारे में वह कहती हैं, 'जब हमने स्क्रीनिंग की थी तो हमारा मकसद था कि इतना बड़ा स्टेप उठाने पर लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा, जो कि काफी अच्छा था। फिर हमने एक बड़ा बदलाव किया कि फिल्म का संगीत पांच भाषाओं में बनाएंगे, क्योंकि फिल्म में डायलॉग नहीं थे तो फिल्म को एक भाषा में रिलीज करना हमें सही नहीं लगा। इसलिए ए.आर रहमान सर ने शुरू से फिल्म का संगीत बनाना शुरू किया। हिंदी के गाने पहले से ही तैयार थे, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी के गाने बनाने शुरू किए। उसमें एक साल और लग गया। लेकिन हमारी मंशा थी कि चाहे एक-दो साल लग जाएं लेकिन जब फिल्म दर्शकों के सामने आए तो लोगों की वाहवाही मिले।

दमण में एनसीडीसी रीजनल अवॉर्ड्स फॉर को-ऑपरेटिव एक्सीलेंस एंड मेरिट-2025 का हुआ आयोजन

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 24 फरवरी। भारत सरकार के को-ऑपरेटिव मंत्रालय के तहत एक कानूनी संस्था नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) ने संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव की प्राइमरी को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एनसीडीसी रीजनल अवार्ड्स फॉर को-ऑपरेटिव एक्सीलेंस एंड मेरिट-2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कचीगाम स्थित विद्युत भवन के सचिवालय में आज अवॉर्ड सेरेमनी आयोजित हुई। इस रीजनल अवॉर्ड्स-2025 के तहत तीन प्राइमरी-लेवल को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को दो कैटेगरी में पहचान के लिए चुना गया। जिसमें बेस्ट प्राइमरी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्स में दानह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के ऋण और ग्राहक सहकारी मंडली लिमिटेड टोकरखाडा- सिलवासा को एक्सीलेंस अवॉर्ड दिया गया। द प्रोग्रेसिव मल्टीपर्पस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड झांपाबार को मेरिट अवॉर्ड दिया गया। डेयरी सेक्टर में बेस्ट प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स में झरी दूध उत्पादक सहकारी मंडली को एक्सीलेंस अवॉर्ड दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को-ऑपरेशन सेक्रेटरी निखिल यू. देसाई ने उपस्थित रहकर अवॉर्ड वितरित किये। साथ ही उन्होंने ज़मीनी स्तर पर आर्थिक विकास को मज़बूत करने और मिलकर विकास के जरिए सदस्यों को मज़बूत बनाने में को-ऑपरेटिव सोसाइटियों की भूमिका की तारीफ की। इससे पहले एनसीडीसी के रीजनल डायरेक्टर संजय कुमार ने गणमान्य लोगों और हिस्सा लेने वालों का स्वागत किया। उन्होंने एनसीडीसी की अलग-अलग स्कीमों के बारे में बताया और रीजनल अवॉर्डस के लिए चुनने के क्राइटेरिया बताए। उन्होंने को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को अपने सदस्यों की पूरी बेहतरी के लिए एनसीडीसी की उदार फाइनेंशियल मदद स्कीमों का फ़ायदा उठाने के लिए बढ़ावा दिया। एनसीडीसी रीजनल कोऑपरेटिव एक्सीलेंस अवॉर्ड-2025 के तहत 35,000 रूपये की रकम दी गई, जबकि एनसीडीसी रीजनल मेरिट अवॉर्ड-2025 के तहत 25,000 रूपये दिए गए। कैश प्राइज़ के अलावा, अवॉर्ड पाने वालों को एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया गया। इस इवेंट में को-ऑपरेटिव रिप्रेज़ेंटेटिव और अधिकारियों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया, जिससे एनसीडीसी का को-ऑपरेटिव एक्सीलेंस को बढ़ावा देने और इलाके में को-ऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का पक्का वादा मजबूत हुआ।

सिंपल काटेला के नेतृत्व में दामिनी वुमेंस फाउंडेशन ने विभिन्न योजनाओं के 300 से अधिक लाभार्थियों का कराया पंजीकरण

■ दामिनी वुमेंस फाउंडेशन के दिलीपनगर सेंटर पर आयोजित कैंप में आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, नेशनल कैरियर सर्विस और ई-श्रम कार्ड का पंजीकरण कराकर दिया गया लाभ ■ भारत सरकार से संबद्ध दत्तोपंथ ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय राजकोट के शिक्षा अधिकारी मोहनचंद सेन और डीएमसी काउंसिलर और दामिनी वुमेंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सिंपल काटेला की मौजूदगी में सेवा कैम्प में उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों, महिला एवं पुरूष कर्मचारियों का मौके पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ लेने हेतु दिया गया मार्गदर्शन

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 24 फरवरी। दामिनी वुमेंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और डीएमसी काउंसिलर सिंपल काटेला के नेतृत्व में दामिनी वुमेंस फाउंडेशन ने भारत सरकार से संबद्ध दत्तोपंथ ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (क्षेत्रीय निदेशालय राजकोट) के सहयोग से 23 फरवरी को दामिनी वुमेंस फाउंडेशन के दिलीपनगर स्थित सेंटर में विशेष कैम्प आयोजित कर 300 अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट (आभा कार्ड), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ई-श्रम कार्ड और नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) हेतु पंजीकरण कराया है। दामिनी वुमेंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सिंपल काटेला और दत्तोपंथ ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (क्षेत्रीय निदेशालय राजकोट) के शिक्षा अधिकारी मोहनचंद सेन ने एनसीएस, आभा कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और ई-श्रमिक कार्ड के रजिस्ट्रेशन कैम्प की शुरूआत की। इस दौरान दत्तोपंथ ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के अधिकारी मोहनचंद सेन ने कैम्प में मौजूद लाभार्थियों को ई-श्रमिक कार्ड, आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और नेशनल कैरियर सर्विस हेतु रजिस्ट्रेशन के फायदे समझाये। सिंपल काटेला का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार ने कमजोर तबकों सहित प्रायः सभी वर्गों के लोगों के हितार्थ योजनाएं बनायी हैं जिससे करोड़ों भारतीय लाभान्वित हो रहे हैं। दामिनी वुमेंस फाउंडेशन के इस कैम्प में मौजूद कंप्यूटर स्टाफ ने उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 300 से ज्यादा महिला-पुरुष श्रमिकों, कर्मचारियों और कामकाजी महिलाओं का आभा कार्ड, ई-श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड और नेशनल कैरियर सर्विस हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। आभा कार्ड लाभार्थी के 14 अंकों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लाभार्थी के प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट और बीमारियों का इतिहास सहित सभी रिकार्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रूप से स्टोर और शेयर करने की सुविधा देती है। यह कार्ड सरकारी और निजी अस्पतालों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना आसान बनाता है। ई-श्रमिक कार्ड भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो 12 अंकों का एक विशिष्ट यूएएन नंबर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षा, बीमा, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंचाना है, जिसमें 2 लाख रुपये का आकस्मिक बीमा शामिल है। जबकि नेशनल कैरियर सर्विस भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। यह पोर्टल नौकरी खोजने, करियर काउंसलिंग, कौशल विकास, व्यावसायिक मार्गदर्शन जैसी सेवाएं मुफ्त में प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। सिंपल काटेला की अगुवाई में दामिनी वुमेंस फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से दमण में कैम्प आयोजित कर आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रमिक कार्ड जैसी योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करती है।

सिलवासा में आयोजित होगा मास्टर क्लास विथ चेस ग्रैंड मास्टर

■ गुजरात के प्रथम शतरंज ग्रैंडमास्टर तेजस बाकरे प्रतिभागियों को शतरंज के महत्वपूर्ण गुर सिखाएंगे

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 24 फरवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव प्रशासन के खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा सिलवासा में मास्टर क्लास विथ चेस ग्रैंड मास्टर कार्यक्रम का आयोजन 27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) सुबह 10:00 बजे किया जा रहा है। संघ प्रदेश में शतरंज खेल को बढ़ावा देने तथा युवाओं में रणनीतिक सोच, एकाग्रता एवं मानसिक कौशल के विकास के उद्देश्य से इस विशेष मास्टर क्लास का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात के प्रथम शतरंज ग्रैंडमास्टर तेजस बाकरे प्रतिभागियों को शतरंज के महत्वपूर्ण गुर सिखाएंगे तथा उनके साथ मैत्री मैच भी खेलेंगे। वे अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव साझा करेंगे और खेल में सफलता के लिए आवश्यक तकनीकी एवं मानसिक तैयारी पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अब्दुल कलाम कॉलेज के पास डोकमरडी, सिलवासा में किया जाएगा। इस मास्टर क्लास में प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शतरंज क्लबों के खिलाड़ी एवं विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। संघ प्रदेश प्रशासन की ओर से सभी शतरंज प्रेमियों, विद्यार्थियों एवं युवा खिलाड़ियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं तथा अपनी प्रतिभा को निखारें। अधिक जानकारी के लिए विभाग के चेस कोच विक्रम मिश्रा से मोबाइल (नंबर 9904901848) पर संपर्क कर सकते है। यह आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने एवं प्रदेश में शतरंज के विकास को नई दिशा देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

गुजरात के 12 जिलों में अगले 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश की आशंका

■ दो मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से बदला मौसम, खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका; किसानों में बढ़ी चिंता

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। 24 फरवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक साथ दो वेदर सिस्टम सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में मावठा पड़ने की चेतावनी जारी की है। इससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका के चलते किसान चिंतित हो गए हैं। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने और दो अलग-अलग सिस्टम के प्रभाव से सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में बारिश का माहौल बना हुआ है। मौसम विभग ने द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, मोरबी, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवल्ली और महिसागर जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्मदा और तापी जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। सुरेंद्रनगर जिले के लखतर तालुका में सोमवार देर रात मौसम में अचानक बदलाव दर्ज किया गया। लखतर के ग्रामीण क्षेत्रों–कडु, ओलक, मालिका, तरमणिया और कलम गांवों में बारिश के झोंके देखे गए। फरवरी महीने में सर्दी की विदाई और गर्मी की शुरुआत के बीच बारिश होने से लोगों को मिश्रित मौसम का अनुभव हो रहा है। वहीं, सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल बारिश का असर बना रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम शुष्क हो सकता है। हालांकि तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। दोपहर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट से ठंड का असर फिर से महसूस किया जा सकता है। फरवरी में हो रही यह बेमौसम बारिश रबी की फसलों जैसे जीरा, गेहूं और राई के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। खासतौर पर खेतों में तैयार खड़ी फसल पर बारिश का पानी गिरने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है। मौसम विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें या तिरपाल से ढंककर सुरक्षित करें, ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके।

खुला कुआं बना मासूमों के लिए मौत का कुआं: दाहोद के झरीबुजुर्ग गांव में दर्दनाक हादसा

■ खेत के पास बने कुएं में गिरने से 5 वर्षीय भाई और 3 वर्षीय बहन की मौत, पूरे गांव में शोक की लहर

दाहोद (ईएमएस)। जिले के गरबाडा तालुका के झरीबुजुर्ग गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। खेत के पास बने खुले कुएं में गिरने से 5 वर्षीय भाई और 3 वर्षीय बहन की करुण मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार, झरीबुजुर्ग गांव के आमली फलिया में रहने वाले मजदूर गोविंदभाई गणावा के 5 वर्षीय पुत्र रोनक और 3 वर्षीय पुत्री आराधना घर के पास खेल रहे थे। खेलते-खेलते दोनों बच्चे खेत के समीप स्थित एक खुले और बिना सुरक्षा दीवार वाले कुएं में गिर गए। घटना की भनक किसी को नहीं लगी। काफी समय तक बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने फलिया और आसपास के क्षेत्र में उनकी तलाश शुरू की। पूरी रात परिवार और ग्रामीण बच्चों की खोजबीन करते रहे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन दोपहर बाद 3 वर्षीय आराधना का शव कुएं में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। पानी निकालने की मशीन से कुएं का पानी खाली किया गया, जिसके बाद 5 वर्षीय रोनक का शव भी बरामद हुआ। सगे भाई-बहन की मौत से परिवार की हालत बेहद दयनीय हो गई है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। ग्रामीणों की मांग है कि खुले कुओं के चारों ओर सुरक्षा दीवार या अन्य सुरक्षा प्रबंध किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

29 मार्च से भावनगर-मुंबई के बीच रोज़ाना दो उड़ानें फिर शुरू

■ इंडिगो 29 मार्च 2026 से एटीआर विमान द्वारा सुबहझ्झशाम दैनिक सेवा देगी, 25 फरवरी से बुकिंग शुरू

अहमदाबाद (ईएमएस)। आगामी 29 मार्च से भावनगर और मुंबई के बीच प्रतिदिन दो उड़ानें पुनः शुरू होने जा रही हैं। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भावनगर से मुंबई की सीधी हवाई सेवा तकनीकी कारणों से पिछले कुछ समय से बंद थी, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों की निरंतर मांग थी। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री निमुबेन बांभणिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के समक्ष प्रभावी प्रस्तुति दी, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप अब 25 फरवरी से इन उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। उडान योजना की समय अवधि पूर्ण होने के कारण बाधित हुई इस हवाई सेवा को बहाल करने के लिए मंत्री महोदय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के.आर. नायडू, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और विभिन्न एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के साथ सिलसिलेवार बैठकें की थीं। केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख और दिशा-निर्देशों के बाद इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 29 मार्च 2026 से भावनगर और नवी मुंबई के बीच एटीआर (एटीआर) विमान के जरिए दैनिक दो उड़ानों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित समय सारणी के अनुसार, भावनगर से नवी मुंबई के लिए उड़ानें सुबह 08:35 बजे और शाम 20:50 बजे प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता के तहत इस सेवा के पुनः प्रारंभ होने से भावनगर के व्यापार और उद्योगों को नई गति मिलेगी। साथ ही, मुंबई के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों के साथ भावनगर की कनेक्टिविटी भी सुगम हो जाएगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर निमुबेन बांभणिया ने केंद्रीय मंत्री के.आर. नायडू, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और विशेष सहयोग के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का आभार व्यक्त करते हुए समस्त भावनगर वासियों को बधाई दी है।

स्वामीः मारुतिनंदन पब्लिक, संपादक, प्रकाशक व मुद्रक विजय जगदीशचंद्र भट्ट द्वारा गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल, नानी दमण - 396210 से प्रकाशित तथा असली आजादी प्रेस गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल नानी दमण - 396210 से मुद्रित।
(समाचारों के चयन के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी पीआरबी एक्ट के अंतर्गत संपादक की होगी। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र दमण न्यायालय के अधीन होगा।)